● वर्ष-3
● अंक-85
रायपुर, शुक्रवार
17 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› रायपुर ग्रामीण में भितरघात...

70 सीटों पर मतदान आज

■ जनता करेगी 1 थर्डजेंडर समेत 958 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर आज 17 नवंबर को दूसरे चरण के तहत चुनाव कराए जाएंगे। गरियाबंद जिले की बिंद्रानवागढ़ सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव होंगे। इस बार दूसरे चरण के चुनाव में डेढ़ करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। दूसरे चरण चुनाव में 1 थर्डजेंडर समेत 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। जनता उनके भाग्य का फैसला कल करेगी। 958 प्रत्याशियों में पुरुष, महिला समेत एक तृतीय लिंग की प्रत्याशी भी मैदान में हैं। 69 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। केवल नक्सल प्रभावित बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केन्द्रों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होंगे।

दूसरे चरण में राज्य के कुल 1 करोड़ 63 लाख 14 हजार 479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 81 लाख 41 हजार 624 है, महिला मतदाता की संख्या 81 लाख 72 हजार 171 है और 684 तृतीय लिंग मतदाता भी शामिल हैं। इसमें 1 थर्डजेंडर समेत 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, जिनमें 827 पुरूष, 130 महिला और 1 तृतीय लिंग प्रत्याशी हैं।

सुगम मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुल 18 हजार 833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों में ही सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराए जाएंगे। इसमें कामरभौदी, आमामोरा, ओढ, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीनकछार और कोदोमाली मतदान केंद्र शामिल हैं। इनके अलावा बिंद्रानवागढ़ के बाकी मतदान केंद्रों में 69 विधानसभा क्षेत्रों समय के अनुसार ही वोट डाले जाएंगे।

विशेष प्रेक्षकों ने हैप्पी वोटिंग पर जोर देने के साथ ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए जांच और कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के बाद छूटे 80 वर्ष या उससे अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मतदान के लिए नियुक्त मतदाता मित्रों की ओर से इन्हें मतदान केन्द्र तक ले जाया जाएगा। परिवहन की सुविधा मुहैया कराए जाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखते हुए उन्होंने प्रत्याशियों को भी इसकी सूचना देने को कहा।

किस पार्टी से कितने प्रत्याशी

भाजपा - 70, कांग्रेस - 70, आप - 45, जेसीसीजे - 60, बसपा - 44, निर्दलीय - 358, गैर मान्यता प्राप्त पार्टी 311 ।विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में भरतपुर-सोनहट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़ , रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिंद्रनवगढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी-बालोद, डौंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे।

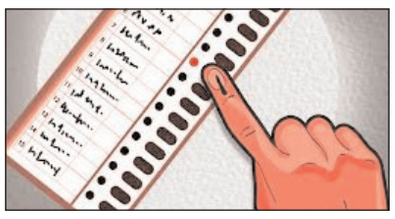

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव- फैक्ट फाइल

दूसरे चरण में कुल मतदाता- 1 करोड़ 63 लाख 14 हजार 479, पुरुष मतदाता - 81 लाख 41 हजार 624, महिला मतदाता- 81 लाख 72 हजार 171, तृतीय लिंग- 684।

सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी फंसे

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। माना जाता है कि समनू नेहामा क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के कारण दो आतंकवादी फंसे हुए थे। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ कुलगाम के दमहाल हांजी पोरा इलाके में शुरू हुई। अक्टूबर में कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे। पुलिस ने कहा कि उनके हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध थे। यह लगभग उसी समय हुआ जब राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के दो जवान घायल हो गए थे। इसके तुरंत बाद, आतंकवादियों का पता लगाने के उद्देश्य से कई दिनों तक घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया ।उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीमें संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ीं, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई।

कैश फॉर पोस्टिंग विवाद में सिद्धारमैया ने किया बेटे का बचाव, कहा- फोन कॉल ऑन था

नईदिल्ली। अपने पिता से उनकी भेजी गई सूची पर काम करने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे के वायरल वीडियो पर राजनीतिक विवाद बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि यतींद्र सिद्धारमैया के साथ चर्चा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में थी। (सीएसआर) फंड और हस्तांतरण के लिए नकद के बारे में नहीं, जैसा कि भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) ने आरोप लगाया है। जद (एस) के एचडी कुमारस्वामी सहित कई विपक्षी नेताओं द्वारा साझा किए गए वीडियो में, यतींद्र को सिद्धारमैया से बात करते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने केवल पांच दिए हैं...विवेकानंद कौन हैं, महादेव... मैंने वह नहीं दिया है। एक्स पर एक लंबी पोस्ट में मुख्यमंत्री ने आरोपों को व्यक्तिगत रूप से उन्हें बदनाम करने का प्रयास बताया और कुमारस्वामी पर परपीड़क मानसिकता का होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने की कुमारस्वामी की कोशिशों को देख रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह हार गई है। अब वह अपने गुप्त राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मेरे परिवार को चोट पहुंचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इससे उनकी परपीड़क मानसिकता उजागर हो गई है ।सिद्धारमैया ने कहा कि कुमारस्वामी के झूठे आरोप और कुछ नहीं बल्कि मेरे बेटे को मानसिक रूप से परेशान करने का उनका क्रूर प्रयास है, जो उनके अनुसार, वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कुमारस्वामी ने पहले कहा था कि यह वीडियो इस बात का सबूत है कि राज्य में पैसे के लिए नौकरी पोस्टिंग, कैश फॉर पोस्टिंग घोटाला चलाया जा रहा है।

भारत का वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मुकाबला देखेंगे पीएम मोदी 19 नवंबर को अहमदाबाद पहुंच सकते हैं

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराने के बाद भारतीय टीम ने फाइनल में एंट्री कर ली है। वहीं अब वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर रविवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं।

मणिपुर में गश्ती दल पर हमला, आईईडी विस्फोट

नईदिल्ली। मणिपुर के टेंग्नौपाल जिले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (ढ्ढश्वष्ठ) हमले के प्रयास में असम राइफल्स के एक गश्ती दल को निशाना बनाया गया। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि लक्षित वाहन में सवार कोई भी कर्मी लगभग 10 विस्फोट में घायल नहीं हुआ। यह घटना सुबह करीब 8.15 बजे टेंगनौपाल जिले के सैबोल के सामान्य क्षेत्र में हुई, जो विभिन्न समुदायों की मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है। असम राइफल्स के एक अधिकारी ने कहा कि हमला अज्ञात विद्रोहियों द्वारा किया गया था ।साईबोल में कंपनी संचालन बेस से 20 असम राइफल्स बटालियन का एक गश्ती दल नियमित क्षेत्र प्रभुत्व गश्त पर निकला था जो गुरुवार सुबह शुरू हुआ था जब यह घटना हुई। सुबह लगभग 8-8.15 बजे, अज्ञात विद्रोहियों के एक समूह ने गश्ती दल पर उस समय हमला करने का प्रयास किया।

सनातन अर्थव्यवस्था का 25 लाख करोड़ का कारोबार

जितेंद्र भारद्वाज

देशभर के बाजारों में इस बार दिवाली के त्योहारी सीजन पर हुई जबरदस्त बिक्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दे दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, त्योहारी सीजन के कारोबार ने यह साबित किया है कि भारत में मनाए जाने वाले त्योहार, देश के व्यापार एवं आर्थिक चक्र को कैसे घुमाते हैं। कैट ने इस आयाम को सनातन अर्थव्यवस्था का नाम देते हुए कहा कि देश के व्यापार के लिए त्योहारों का मनाया जाना बेहद ही महत्वपूर्ण है।

एक अनुमान के अनुसार, देश में प्रति वर्ष सनातन अर्थव्यवस्था का यह कारोबार लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। यह आंकड़ा, देश के कुल रिटेल कारोबार का लगभग 20 फीसदी है। यह बेहद स्पष्ट है कि भारत में त्योहार, तीर्थ आदि के कारण बहुत बड़ी धनराशि बाजार चक्र में पहुंचती है। यह

राशि, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है।

रोजगार एवं स्व-व्यापार का बड़ा अवसर: कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, इस कारोबार के मद्देनजर भारत के व्यापारी वर्ष भर में होने वाले विभिन्न त्योहारों के लिए अपनी दुकानों में विशिष्ट प्रबंध करते हैं। खासतौर पर त्योहारी सीजन में बड़ा व्यापार होता है। त्योहारों से देशभर में रोजगार तथा स्व-व्यापार के बड़े अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इसके जरिए मध्यम एवं निम्न वर्ग का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। एक अनुमान के अनुसार देश में प्रति वर्ष सनातन अर्थव्यवस्था का यह कारोबार लगभग 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसे देश के कुल रिटेल कारोबार का लगभग 20 फीसदी कहा जा सकता है। सनातन अर्थव्यवस्था की व्याख्या करते हुए दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा, नवरात्रि से लेकर दीवाली के दिन तक देश के मेन लाइन रिटेल व्यापार में 3.75 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। वहीं देश भर में दुर्गा पूजा और इसके आस पास हुए अन्य त्योहारों में लगभग 50 हजार करोड़ का व्यापार हुआ है। गणेश चतुर्थी के दस दिवसीय समारोह के दौरान 20-25 हजार करोड़ रुपये का कारोबार देखा गया है।

बतौर खंडेलवाल, यह आंकड़े तो सिर्फ 3 त्योहारों के हैं। इसी तरह से होली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और राखी जैसे अन्य ढेरों त्योहारों पर बाजारों में हुई व्यापक खरीदी को भी जोड़ा जाए, तो कई सौ लाख करोड़ रुपये, सनातन व्यापार में जुड़ जाएंगे। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश भर में लगभग 10 लाख से अधिक मंदिर हैं।

जांजगीर-चांपा सीट पर नारायण चंदेल चौथी बार मारेंगे बाजी?

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के बीचो-बीच स्थित जांजगीर-चांपा को प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। कोसा, कांसा और कंचन की नगरी जांजगीर चांपा विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण दिलचस्प देखने को मिलते हैं। जांजगीर चांपा जिले में तीन विधानसभा सीट अकलतरा,जांजगीर चांपा,पामगढ़ है। पामगढ़ विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी दोनों सीट सामान्य के लिए सुरक्षित है। विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार जांजगीर चांपा हाई प्रोफाइल वीआईपी सीट बन चुकी है। क्योंकि यहां से छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रत्याशी नारायण चंदेल चुनावी रण में है। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। व्यास कश्यप लंबे समय तक बीजेपी में रह चुके हैं। इसके बाद साल 2018 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। अब इस बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है।

वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल यहां से विधायक हैं। उनके बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ एक आदिवासी शिक्षिका ने दुष्कर्म और गर्भपात का केस दर्ज कराया था। हालांकि सितंबर 2023 में हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर चुका है। इस केस की वजह से विधायक नारायण चंदेल और उनके बेटे के छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।जांजगीर-चांपा सीट सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है।

एक उप चुनाव समेत अब तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं। जिनमें 11 बार कांग्रेस जीती है, जिनमें एक उपचुनाव सहित पहले तीन चुनाव में रामकृष्ण राठौर और बिसाहूदास महंत, उनके बेटे चरणदास महंत और बीजेपी के नारायण चंदेल ने तीन बार विधायक रह चुके हैं। चंदेल अविभाजित मध्यप्रदेश में 1998 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वर्ष 2008 में दूसरी बार अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याषी मोतीलाल देवांगन को 1190 मतों से हराकर विधायक चुने गए और उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। वर्ष 2018 में वे तीसरी बार यहां के विधायक बने हैं और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यहां की आबादी में कश्यप, कुर्मी समाज का 55 फीसदी हिस्सा है। यहां कुल 1 लाख 97 हजार 32 मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 1 हजार 137 पुरुष और 95 हजार 895 महिला मतदाता और 11 थर्ड जेंडर वोटर्स है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद कांग्रेस को दो बार यहां से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। इस सीट पर सर्वाधिक लीड लेने का रिकार्ड डॉ. चरणदास महंत के नाम दर्ज है। चांपा विधानसभा के पड़ोस में बलौदा विधानसभा सीट हुआ करती थी, जिसमें सबसे कम उम्र का विधायक बनने का रिकार्ड लखेश्वर पालीवाल के नाम अंकित है। यहां बीजेपी और कांग्रेस में चुनावी जंग देखने को मिलती है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के नेता सीट बदलते रहते हैं। जांजगीर चांपा विधानसभा किसान बहुल्य क्षेत्र है। क्षेत्र का 80 फीसदी भाग नहर के पानी पर निर्भर है। किसान खरीफ फसल के तौर पर धान उगाकर और फिर उसे सरकार को बेचकर लाभ कमाते हैं, लेकिन रबी की फसल में परिवर्तन ना करके वापस धान उगाते हैं। दूसरी फसल के उत्पादन को सरकार नहीं खरीदती।

जातीय समीकरण- इस सीट में ओबीसी और एससी मतदाताओं का दबदबा कायम है। इसी सीट पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अधिक हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग जीत और हार का समीकरण तय करते हैं। इसके अलावा कुर्मी, कश्यप, साहू, राठौर जाति भी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के वोटर भी कम होने के बाद भी किसी भी प्रत्याशी के लिए दोनों वर्गों का वोट अहम है। जांजगीर चांपा विधानसभा में 212297 मतदाता हैं, जिसमें से 104631 महिला और 107653 पुरुष मतदाता हैं।

भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है बिलासपुर की स्विंग बेल्ट

बिलासपुर। बिलासपुर संभाग की 25 सीटों पर 17 नवंबर यानी शुक्रवार को मतदान होगा। कांग्रेस और भाजपा इस क्षेत्र में जोर-आजमाइश कर रही हैं, जो 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा में लगभग एक तिहाई विधायकों को भेजता है। राज्य के पांच प्रशासनिक संभागों में से मध्य क्षेत्र में स्थित बिलासपुर संभाग में सबसे अधिक 25 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो इस बार विजेता का फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

विशेष रूप से यह एकमात्र प्रभाग था, जिसे कांग्रेस 2018 में नहीं जीत पाई थी। जबकि भाजपा ने इस क्षेत्र में अपनी लगभग आधी सीटें जीत लीं। 2018 में संभाग में 24 सीटें थी, जिनमें से कांग्रेस ने 12 जबकि भाजपा ने सात सीटें जीतीं। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने दो और तत्कालीन अजीत जोगी के नेतृत्व वाली जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) ने तीन सीटें जीतीं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ के नए जिले के निर्माण के बाद, बिलाईगढ़ सीट, जो पहले रायपुर संभाग में थी, बिलासपुर संभाग में शामिल कर दी गई। 2018 में बिलाईगढ़ सीट कांग्रेस ने जीती थी.

इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी

2018 में दो सीटों पर दूसरे स्थान पर रहने वाली बसपा ने इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) के साथ गठबंधन किया है। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस बार बिलासपुर संभाग में प्रचार के लिए अपने शीर्ष बंदूकें तैनात कीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्षेत्र में रैलियां कीं।

बिलासपुर संभाग में शामिल हैं ये जिले

संभाग में पांच जिले रायगढ़ (लैलुंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़ की विधानसभा सीट), कोरबा (रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही सीट), बिलासपुर (कोटा, तख्तपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी), जांजगीर-चांपा (अकलतारा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजपुर, पामगढ़), मुंगेली (लोरमी और मुंगेली) और सारंगढ़-बिलाईगढ़ (बिलागढ़ सीट) शामिल हैं। इनमें से तीन सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और पांच सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

बूथ की तरफ रवाना हो रहे मतदान दल

बालोद-महासमुंद। बालोद जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए मतदान सामग्री वितरण किया गया और टीम को रवाना किया गया। मतदान दल के अधिकारी, कर्मचारी मतदान सामग्री स्थल में पहुंचकर निर्धारित काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त की। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने मतदान कर्मियों से बातचीत कर जानकारी भी ली।

बालोद कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मतदान कर्मियों को रवाना करने के साथ ही बालोद जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वह लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी जरूर बनाएं। बालोद हमेशा से ही सभी चीजों में अव्वल रहा है और मतदान के आंकड़ों में भी बालोद अव्वल रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं आम जनता के हिसाब से हैं।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि बालोद जिले के तीनों विधानसभा सीटों में प्रत्येक विधानसभा में 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं।

वहां की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होगी। तैयारी पूरी हो चुकी है और यह उत्साहवर्धन के लिए मिल का पत्थर साबित होगी। महिला मतदान कर्मी भी बेहद खुश हैं और खुशी-खुशी अपने संगवारी मतदान केंद्र को रवाना हुए हैं।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि बालोद जिले के विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांग मतदान केंद्र एक युवा मतदान केंद्र भी बनाया गया है। युवा मतदान केंद्र में केवल युवा ही मतदान कर्मियों की भूमिका निभाएंगे। वहीं, दिव्यांग मतदान केंद्र में दिव्यांगों की जरूरत को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी है।

महासमुंद जिले के चारों विधानसभा के लिए मतदान दल रवाना हुए हैं। पिटियाझर के मंडी परिसर में गुरुवार सुबह से ही मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा था। मंडी परिसर पहुंचकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने जायजा लिया। सामग्री वितरण के लिए मंडी परिसर पीटियाझर में 16-16 काउंटर बनाए गए। मतदान सामग्री लेकर 235 रूटों के लिए 12,295 कर्मचारी रवाना हुए। जिले के चारों विधानसभा में कल 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए जिले में 1079 मतदान केंद्र बनाये गए। 8 लाख 55 हजार 503 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ मे दूसरे चरण के होने वाले मतदान के लिए मुंगेली जिले के कलेक्टर राहुल देव और एसपी चंद्रमोहन सिंह ने आदर्श मतदान केंद्र स्वामी आत्मानन्द इंग्लिश मीडियम स्कूल का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि मतदान दलों को रवाना एवं मतदान सामाग्री वितरण की प्रकिया शुरू हो चुकी है। मुंगेली जिले में 659 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मुंगेली में 279 तो लोरमी में 262 मतदान केंद्र बनाए गए है। इसके साथ ही जिले में पांच लाख 86 हजार मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं, सभी विधानसभा में संगवारी मतदान केंद्र तो एक एक दिव्यांग मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

फसल कटने के बाद स्लरी पाइप लाइन का काम जोर-शोर से हुआ शुरू

जगदलपुर। किरन्दुल से नगरनार स्टील प्लांट तक लौह अयस्क पहुंचाने स्लरी पाइपलाइन बिछायी जा रही है। इसके साथ ही कस्तूरी में लौह अयस्क को पैलेटाइजेशन करने के लिए 2 एमटीपीए का पैलेट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण भी अब जोर-शोर से चल रहा है। विदित हो कि नगरनार स्टील प्लांट के समीप कस्तूरी में निर्माणाधीन पैलेट प्लांट और नगरनार से किरन्दुल तक बिछायी जा रही स्लरी पाइप लाइन का काम हर हाल में 2024 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कई जगहों पर बाड़ी व खेतों से होकर पाइप लाइन गुजर रही है, इसके कारण बरसात में खेतों में फसल लगे होने के कारण काम ठप हो गया था, अब फसल कटने के बाद जोर-शोर से काम शुरू किया गया है।

उल्लेखनीय है कि किरन्दुल से नगरनार तक 15 एमटीपीए की स्लरी पाइपलाइन बिछायी जा रही है, जिसमें से कस्तूरी में 02 एमटीपीए लौह अयस्क को पैलेटाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद शेष लौह अयस्क को विशाखापटनम तक परिवहन करने आगे फिर स्लरी पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल किरन्दुल से नगरनार तक ही पाइपलाइन बिछायी जा रही है। किरन्दुल से नगरनार तक तीन चरण में

काम किया जा रहा है, और पहले व दूसरे चरण में काफी काम हो चुका है। अब स्टील प्लांट में उत्पादन चल रहा है, इसके कारण पैलेट प्लांट और नगरनार से किरन्दुल तक स्लरी पाइपलाइन सड़क किनारे से गुजर रही है।

वर्तमान में स्टील प्लांट में लौह अयस्क की आपूर्ति मालगाड़ी ज़े माध्यम से की जा रही है। नगरनार स्टील प्लांट को प्रतिवर्ष करीब 10 मिलियन टन लौह अयस्क की जरूरत पड़ेगी। यही कारण है कि एनएमडीसी द्वारा रेललाइन के साथ-साथ स्लरी पाइप लाइन बिछायी जा रही है। प्लांट में दोनों ही परिवहन माध्यम से लौह अयस्क का परिवहन किया जाएगा। फिलहाल मालगाड़ी के माध्यम से ही लौह अयस्क की आपूर्ति की जा रही है। आमागुड़ा स्टेशन से लेकर स्टील प्लांट के भीतर तक करीब 52 किलोमीटर लंबी रेललाइन बिछाई गयी है। स्टील प्लांट ज़े भीतर दर्जनभर साइडिंग का भी निर्माण किया गया है।

सूर्योपासना के चार दिवसीय छठ पूजा-सूर्य षष्ठी की शुरुआत आज से

जगदलपुर। सूर्योपासना का चार दिवसीय छठ पूजा-सूर्य षष्ठी की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की षष्ठी तिथि 17 नवंबर नहाय खाय के साथ होंगी। छठ पूजा को लेकर बांस से बने सूप और अन्य सामग्रियों की मांग को लेकर बाजारों में मांग बढ़ गई है, लोग छठ को लेकर खरीददारी कर रहे हैं। इस वर्ष भी बांस के बने सूप का मूल्य बढ़ गए हैं। छठ पूजा में बांस से बने सूप और टोकरी का अपना महत्व होता है। हिंदू पंचाग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर को नहाय खाय के साथ होगी, 18 नवंबर को खरना, 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य, 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिए जाने के साथ ही छठ पर्व का परायण होगा।

उल्लेखनिय है कि छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोकपर्व है। यही एकमात्र ऐसा त्योहार है, जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। वैसे भी हिन्दू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। सभी वैदिक-धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत में पंचदेवता की पूजा होती है, जिनमें सूर्य भी एक हैं। छठ महापर्व में भी सूर्यदेव के लिए व्रत किया जाता है और उनकी पूजा होती है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ का यह व्रत संतान-प्राप्ति एवं उनके सुखी एवं स्वस्थ जीवन के लिए किया जाता है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत होती है। छठ महापर्व में मुख्यत- सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं, जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। सूर्य देव के साथ-साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय भाषा में छठी मैंया कहा जाता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

दो ट्रकों की भिड़ंत में 11 केवी का टॉवर धराशायी

बिलासपुर। गुरुवार को बिलासपुर रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में कोनी से कुछ दूर आगे ग्राम सेंदरी के पास दो ट्रैकों के बीच भिड़ंत हो गई ।इस भिड़ंत में किसी जान नहीं गई और अलबत्ता 11 के वी का विद्युत टावर धराशाई हो गया जिसके चलते इस मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और चलते परिर्वतित मार्ग से यातायात को शुरू किया गया। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार दोनों ट्रकों के मध्य आमने-सामने से जोरदार टक्कर हुई जिसमें सड़क किनारे लगे 11 के वी विद्युत टावर से ट्रक टकरा गई जिससे 11 केवी का यह टॉवर भरभराकर सड़क पर ही गिर गया। इस ट्रक दुर्घटना में एक चालक घायल हुआ है, जिसे कोनी पुलिस ने रेस्क्यू कर सिम्स में भर्ती कराया है। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद तत्काल इसमें विद्युत प्रवाह को बंद किया गया और बिजली विभाग का अमला और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क पर गिरे डिस्कनेक्ट कर टावर को हटाने का कार्य किया जा रहा है।

चुनावी बहस से नाराज पड़ोसी ने बुजुर्ग पर किया हमला

कांकेर। पखांजुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 में बुजुर्ग रवि हालदार को पड़ोसी गौर हालदार ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया है, हमले में रवि हालदार के गर्दन पर गहरी चोट लगी हैं। जिसे गुरूवार को पखांजूर सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 नवंबर को हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव के चर्चा के दौरान दोनों में आपसी बहस हो गई इस दौरान एवं आवेश में आकर पड़ोसी गौर हालदार ने कुल्हाड़ी से रवि हालदार पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही कर रही है।

सीआरपीएफ कैंप के स्विमिंग पूल में डूबने से एक की मौत

जगदलपुर। करनपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में बने स्विमिंग पूल में डूबने से चार वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। सीआरपीएफ कैंप के जवानों का कहना था कि स्विमिंग पूल में काम चलने के कारण उसे ताला लगा दिया गया है, लेकिन बच्चे किस तरफ से स्विमिंग पुल में गए, इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस घटना के बाद से परिजनों का बुरा हाल है, वही कैंप में मातम छा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज गुरूवार सुबह सीआरपीएफ 201 कोबरा बटालियन में कांस्टेबल के पद में पदस्थ राहुल राठौर का पुत्र पीयूष राठौर चार वर्ष कैंप के अंदर बने स्विमिंग पूल में खेलने गया हुआ था। बच्चे को काफी देर तक नहीं दिखने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। कैंप के कुछ बच्चों ने बताया कि आए दिन कैंप के अंदर स्विमिंग पूल में सभी बच्चे नहाने व खेलने के लिए जाते हैं, जिसके बाद जब परिजन स्विमिंग पूल पहुंचे तो उन्होंने बच्चे को औधे मुंह पानी में डूबा हुआ देखा, जिसके बाद बच्चे को बाहर निकाला गया।

खड़ी स्कॉर्पियो वाहन में लगी आग जलकर हुई खाक

जगदलपुर। थाना कोतवाली क्षेत्र अंर्तगत सनसिटी कॉलोनी में खड़ी एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। वाहन में आग लगते ही कॉलोनी के लोगों ने इसकी सूचना दमकल कर्मियों को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी स्कॉर्पियो वाहन जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि जिस स्कॉर्पियो में आग लगी थी, वह पिछले कई दिनों से यहां खड़ी थी। गाड़ी में आग कैसे लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया ता, तब तक पूरी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। गाड़ी का मालिक कौन है और यह गाड़ी कॉलोनी में क्यों खड़ी थी, पुलिस इसकी जांच कर रही है।

दुर्ग में अस्पताल से फरार हुआ कैदी

दुर्ग। हत्या व लूट के मामले में विचाराधीन बंदी जिला अस्पताल से फरार हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती बंदी टॉयलेट करने गया। इस दौरान दो नकाबपोश वहां पहुंचे और जेल प्रहरियों के साथ मारपीट कर बंदी को अपने साथ ले गए। नकाबपोशों ने प्रहरियों का मोबाइल भी लूट लिया। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने धारा 224, 392 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, विचाराधीन बंदी अभिषेक उर्फ अनुपम झा निवासी बैकुंठपुर, जिला-वैशाली (बिहार) को हत्या के एक मामले में जेल भेजा गया। अनुपम अम्लेश्वर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप संचालक सुरेंद्र सोनी की गोली मारकर हत्या कर दुकान में रखे सोने चांदी के जेवरात को लूट कर फरार हो गया था। अनुपम के खिलाफ थाना अमलेश्वर में मुकदमा दर्ज किया गया था औ 29 अक्तूबर 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस ने इस मामले में सौरभ सिंह, अभय भारती, आलोक यादव, अभिषेक झा को बनारस से गिरफ्तार किया था।

सियासी पावर हाउस में स्पीकर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, मंत्रियों व जोगी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर

बिलासपुर। प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला बिलासपुर संभाग खनन उद्योगों के साथ विद्युत उत्पादन और सियासत का भी पावर हाउस है। यहां विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, दो मंत्रियों उमेश पटेल व जयसिंह अग्रवाल मैदान में हैं। पूर्व सीएम अजीत जोगी की पत्नी डॉ. रेणु जोगी, बहू ऋचा जोगी, आईएएस से राजनेता बने ओपी चौधरी और लखीराम अग्रवाल के पुत्र पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी मैदान में हैं। कई सीटों पर बसपा और जेसीसीजे के मजबूत दखल से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।

शहरों में अधिकतर गैरप्रांत के बाशिंदे हैं, जबकि गांवों में पिछड़ा, आदिवासी और अनुसूचित जाति की बहुलता है। शहरी रोजगार, मूलभूत सुविधाओं के विकास और घोटालों को मुद्दा मानते हैं। ग्रामीण मतदाता घोषणापत्रों में हित तलाश रहे हैं। पिछले चुनाव में संभाग की 24 में से 12 कांग्रेस, 7 भाजपा और 3 जेसीसीजे और 2 बसपा के खाते में थीं। इस बार बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ और रायगढ़ के सारंगढ़ को नया जिला बनाने से संभाग में सीटों की कुल संख्या 25 हो गई है।

शहर के मगरपारा इलाके में मिले ऑटो रिक्शा चालक आकाश वैष्णव ने बताया, वह कोटा क्षेत्र के रहने वाले हैं। कर्जमाफी, धान का समर्थन मूल्य, भूमिहीनों और महिलाओं को सालाना भत्ता देने जैसी खुद के तात्कालिक फायदे की योजनाएं और उनका सीधा लाभ उन्हें मिलेगा, वह उसी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ललित देवांगन आगे आकर बोले, पहले अपना घर दुरुस्त कर लें, फिर बाहर की सोचेंगे। यह जरूर कहा कि बेरोजगारी भत्ते की जगह काम के बदले मेहनताना मिले तो बेहतर संदेश जाएगा। सरकार को इसके लिए युवाओं को तैयार करना चाहिए।

सक्ती सीट पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के सामने भाजपा के खिलावन साहू हैं। पिछले चुनाव में महंत ने भाजपा ने मेधाराम साहू को 30 हजार से अधिक वोटों से हराया था। इस सीट पर ओबीसी मतदाता निर्णायक हैं। कांग्रेस के सत्ता में बने रहने पर महंत का नाम भी सीएम पद की चर्चा में शामिल है।

लोरमी सीट से चुनाव लड़ रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के संदर्भ में चर्चा है कि भाजपा आई तो सीएम ओबीसी वर्ग से होगा। साहू समाज के अरुण के खिलाफ कांग्रेस ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू को मैदान में उतारा है। वैसे इन दो सीटों पर आमने-सामने की लड़ाई है पर बड़े चेहरों से उम्मीदें भी बड़ी हैं।

बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड के पास रविकांत त्रिपाठी ने बताया, वह कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद बेरोजगार हैं। सैकड़ों कंपनियां होने के बाद भी नौकरी दिलाने की गारंटी सरकार नहीं लेती। खुद का काम शुरू किया है, लेकिन उम्मीद के अनुरूप काम नहीं नहीं मिल रहा। बोले, यह सरकार तो नौकरियों के लिए भी पाक-साफ भर्तियां नहीं कर सकी। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल से तुलना करें तो कांग्रेस के ये पांच साल हमारी उम्मीदों को रौंदते रहे।

आईएएस से भाजपा नेता बने ओपी चौधरी रायगढ़ सीट से मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस से विधायक प्रकाश नायक हैं। चौधरी को पिछले चुनाव में खरसिया से हार का सामना करना पड़ा था। पिछले दिनों सभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप इन्हें चुनाव जिता दें तो मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। शाह के बयान से चौधरी क्षेत्र में चर्चा का विषय हैं। प्रदेश के मंत्री उमेश पटेल इस बार भी खरसिया से और जयसिंह अग्रवाल कोरबा सीट से हैं। बिलासपुर सीट से रमन सरकार में मंत्री रहे अमर अग्रवाल एक बार फिर से मैदान में हैं। पिछले चुनाव में उन्हें कांग्रेस के शैलेष पांडेय ने यूपी और बिहार के मतदाताओं के सहारे 11 हजार से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी।

जेसीसीजे से प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी कोटा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। यहां से भाजपा ने दिलीप सिंह जूदेव के पुत्र प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में लगभग तीन हजार वोटों से जीतीं रेणु जोगी की राह इस बार आसान नहीं है। जोगी की बहू ऋचा जोगी अकलतरा विधानसभा से मैदान में हैं। उनके खिलाफ भाजपा से विधायक सौरभ सिंह हैं। पिछले चुनाव में ऋचा लगभग 18 सौ वोटों से चुनाव हार गई थीं। कांग्रेस यहां बड़े अंतर से तीसरे स्थान पर रही थी। इस बार भी यहां आमने-सामने की लड़ाई है। अजीत जोगी के बिना परिवार के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने की चुनौती है।

बसपा को यहां जांजगीर-चांपा और आसपास के क्षेत्र से हर चुनाव में दो सीटों पर जीत मिलती रही है। हालांकि, वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2008 के चुनाव में बसपा को 6.1 फीसदी वोट मिले थे। पिछले चुनाव में यह प्रतिशत 3.87 रह गया।

संभाग में सीटों की कुल संख्या 25 है। कांग्रेस विधायकों की संख्या 14 हो गई। जेसीसीजे के विधायक धर्मजीत सिंह भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा की सीटें आठ हुईं और जेसीसीजे की सिर्फ एक रह गई।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में थमा चुनावी प्रचार, सीएम बघेल ने पोते के साथ की चहलकदमी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। यह मतदान राज्य की 70 विधानसभों सीटों पर होगा। वहीं, राज्य में चुनावी प्रचार-प्रसार अब खत्म हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज लगातार चुनाव प्रचार और रोड शो के बाद जब घर पहुंचा तो अभी हाल-हाल स्वयं चलना सीखे पोते विवांश आज मेरे कैप्टन बन गए और स्वयं मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाया। चहलकदमी ने मेरी पूरी थकान मिटा दी। वहीं, पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। जनसंपर्क के दौरान रमन सिंह ने कहा कि दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होगा। 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। राज्य और देश में अच्छी सरकार का चयन करें।

पैसे बांटने, पोस्टर फाड़ने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ता

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की चुनाव होने में एक ही दिन बचे हैं। सभी राजनितिक पार्टियों का प्रचार-प्रसार थम गया है। इस बीच बीते दिनों बुधावर को देर शाम कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भापजा के कुछ लोग पैसा बांटने और पोस्टर फाड़ने के काम कर रहे थे। इस तरह के काम से उनको मना करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाली-गलौज किया। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं थाने में पूछताछ के दौरान दोनों गुटों में मारपीट भी हुई। मामला सरस्वती नगर थाने क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यह विवाद रात को कोटा के टीचर कॉलोनी से शुरू हुई थी। इसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ गई। इस दौरान थाने में मारपीट भी हुई है। वहीं दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस विषय में थाने में दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली गई है। सीएसपी मयंक गुर्जर ने इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भवानी नगर के इलाके में विवाद होने और प्रत्याशी की पोस्टर फाड़े जाने की शिकायत मिली थी। इसे लेकर दो राजनीतिक पार्टियों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस की टीम ने मामले को शांत कराया है। दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच जारी है।

चुनाव को लेकर शराब की दुकानें बंद बेचते पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजधानी रायपुर में सभी शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। सभी शराब दुकानों को 17 नवंबर तक बंद किया गया है। वोटिंग को ध्यान में रखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे नरेन्द्र ने मदिरा दुकानों को बंद रखने के लिए आदेश जारी किया है। इस विषय में आबकारी विभाग ने जिला प्रशासन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को जानकारी देते हुए सभी मदिरा दुकानों को बंद कर दिया है। चुनाव को देखते हुए बीते दिनों बुधवार से सभी मदिरा दुकानों को बंद कर दिया गया है। विधानसभ 2023 चुनाव को शांतिपूर्वक करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस समय में किसी भी प्रकार के अवैध शराब बिक्री करने पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें देशी मदिरा दुकाने, विदेशी मदिरा दुकाने, होटलबार, असैनिक विनोदगृह भी बंद रखे जाने के आदेश दिए हैं। उक्त अवधि में मदिरा की कोई भी दुकान, रेस्ट्रोरेन्ट, होटल, क्लब और मदिरा बेचने की अनुमति नहीं है।

रायपुर का ये विधानसभा रचने जा रहा इतिहास

सारे बूथों में सुरक्षा से लेकर मतदान कराने की जिम्मेदारी होगी महिलाओं के हाथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ की रायपुर उत्तर विधानसभा में शुक्रवार 17 नवंबर को होने जा रहा मतदान निर्वाचन के इतिहास में एक दुर्लभ अविस्मरणीय और बेहद गौरवपूर्ण उपलब्धि जोड़ जाएगा. आजाद भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पूरे विधानसभा में निर्वाचन का भार संभालने वाली महिलाएं ही हैं. यहां 201 मतदान केंद्र हैं और सभी संगवारी बूथ हैं. यहां पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान अधिकारी तक सभी महिलाएं ही हैं. इस महती कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से 804 महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और लगभग 200 महिलाएं रिजर्व रखी गई हैं.

इस विधानसभा की आब्जर्वर भी एक महिला आईएएस अधिकारी विमला आर हैं. उनकी लायजनिंग अधिकारी भी महिला ही हैं. अधिकांश बूथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ही जिम्मे हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी आईएएस

आफिसर रीना बाबा साहब कंगाले ही हैं.

कल उत्तर रायपुर विधानसभा के मतदाता जब मतदान केंद्र में प्रवेश करेंगे तो मतदाता पर्ची चेकर करने से लेकर रजिस्टर में हस्ताक्षर कराने से लेकर ऊंगली में स्याही लगाने का काम पूरी तरह महिलाओं के जिम्मे ही होगा. 201 बूथों में इतनी ही महिला पीठासीन अधिकारी होंगी और 603 मतदान अधिकारी होंगी.

उल्लेखनीय यह भी है कि छत्तीसगढ़ के समाज में लैंगिक समानता गहराई से बसी हुई है और प्रदेश का लिंगानुपात इसकी गवाही देता है. रायपुर उत्तर विधानसभा में जहां सभी बूथों पर महिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वहां पर लिंगानुपात 1010 है अर्थात प्रत्येक हजार पुरुष के पीछे 1010 महिलाएं हैं.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस संबंध में बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होते ही हमें यह विचार आया कि क्यों न जिले की एक विधानसभा में निर्वाचन का पूरा दायित्व महिलाओं को सौंपा जाए. सभी ने इस विचार को सराहा, फिर हमने इसकी योजना बनाई. आज सुबह जब मतदान दल अपने गंतव्य केंद्रों के लिए रवाना होने पहुंचे तो उनका उत्साह देखकर बहुत खुशी हुई. उन्होंने हमें बताया कि यह ऐतिहासिक अवसर है जब पूरी टीम महिलाओं की है और हम इतने महत्वपूर्ण दायित्व को अकेले ही पूरा करेंगी.

कलेक्टर भुरे ने बताया कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में भी आधे बूथों पर महिला अधिकारी ही होंगी. इस तरह रायपुर उत्तर और रायपुर दक्षिण विधानसभा में महिलाओं के हाथों निर्वाचन की महत्वपूर्ण कमान होगी.

इस संबंध में चर्चा करने पर मतदान दल से जुड़ी निशा रामटेके ने बताया कि हम लोगों के लिए यह बहुत सुखद अवसर है. ट्रेनिंग में भी सारी महिलाएं ही थीं और अब हमारा मतदान दल भी महिलाओं का है. हम सब बहुत अच्छे से और समन्वय से यह कार्य पूरा कर सकेंगे.लीला पटेल ने कहा कि महिलाओं पर भरोसा जताया गया है ये बहुत अच्छी बात है. हो सकता है कि कुछ लोगों को संदेह हो कि पुरुष सहयोगी नहीं होंगे तो महिलाओं को दिक्कत हो सकती है. कल यह साबित हो जाएगा कि महिलाएं भी अकेले ही हर महत्वपूर्ण दायित्व पूरा कर सकती हैं.

दूसरे चरण की 70 सीटों पर आज, मतदाता करेंगे 958 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान होना है. मतदान के एक दिन पहले गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे चरण के मतदान को लेकर जानकारी साझा की. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण की 70 में से 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 5 बजे और बाकि की 61 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए 958 प्रत्याशी मैदान में है, इनमे से एक तृतीय लिंग प्रत्याशी भी शामिल है. इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल 1 करोड़ 63 लाख 14 हजार 479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर करेंगे. राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से डबल श्वङ्करू मशीन दी गई है. इन मतदाताओं में 2,160 ऐसे मतदाता है जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है. मतदान के लिए पूरे राज्य में 18 हजार 833 मतदान केंद्र बनाए गए है, जिनमे 9 हजार से भी ज़्यादा मतदान केंद्रों की सीधा लाइव निगरानी होगी. मतदान के लिए 90 हज़ार 272 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है.

71 दिव्यांग और 10 पिंक मतदान केंद्र

रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया विशेष मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हर विधानसभा में 10 पिंक मतदान केंद्र बनाए गए है जिनमे महिला कर्मचारी तैनात रहेगी।

मतदान के लिए अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र निर्धारित

रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान के समय सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, वे वोट डालने हेतु मतदान केन्द्रों पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएगे, किन्तु जो मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते वे दूसरे वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत कर वोट डाल सकेंगे। वैकल्पिक पहचान पत्र के रुप निर्धारित किए गए पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्र/राज्य शासन अथवा सार्वजनिक लोक उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किया जाने वाला फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी की गई स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, विधायक, सांसदों, विधान परिषद, सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि शामिल है, इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

लोकतंत्र के यज्ञ में मतदाता आज देंगे वोट की आहूती

■ **सबसे अधिक मतदाता रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, रायपुर पश्चिम में सबसे अधिक प्रत्याशी**

रायपुर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए रायपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18 लाख 84 हजार 926 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सबसे अधिक रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख 49 हजार 316 मतदाता है। विधानसभा रायपुर पश्चिम में दो लाख 91 हजार 538 मतदाता, रायपुर नगर दक्षिण में दो लाख 59 हजार 948 मतदाता, धरसीवां विधानसभा में 2 लाख 34 हजार 663, आरंग विधानसभा में 2 लाख 31 हजार 327, अभनपुर विधानसभा में 2 लाख 13 हजार 936 और बलौदाबाजार विधानसभा के रायपुर जिले में शामिल क्षेत्रों में 1 लाख 2 हजार 48 मतदाता कल अपना प्रतिनिधि चुनने वोट डालेंगे और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में सहभागी बनेंगे। जिले में इस बार 397 सर्विस वोटर, 11 हजार 734 पीडब्ल्यूडी वोटर और 80 साल से अधिक उम्र के 20 हजार 526 वोटर भी मताधिकार का उपयोग करेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में इस बार महिला मतदाताओं की विशेष सहायता तथा सहूलियत के लिए संगवारी /आदर्श मतदान केंद्र भी बनाये गये है। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी 201 मतदान केन्द्रों में इस बार महिलायें ही वोटिंग

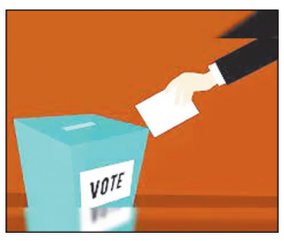

करायेंगी। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य छह विधानसभा क्षेत्र में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाये गये है। यहा पीठासीन अधिकारी से लेकर अन्य मतदान कर्मचारी एवं सुरक्षा महिलाओं के हाथ में होगी। यहा महिला मतदाता आसानी से वोट डाल सकेगी।

विधानसभा निर्वाचन के लिये जिले में कुल 1878 मतदान केंद्र बनाये गये है। धरसीवां विधानसभा में 251, रायपुर ग्रामीण में 307, रायपुर पश्चिम में 265, रायपुर उत्तर में 201, रायपुर दक्षिण में 255, रायपुर आरंग में 249, अभनपुर में 240 और बलौदाबाजार विधानसभा में शामिल क्षेत्र में 110 मतदान केन्द्र बनाये गये है।

विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी मतदान केन्द्रों में व्हीलचेयर, स्टीक, रैम्प की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। मतदान दिवस में दिव्यांग एंव अधिक उर्म्र के वृद्ध मतदाताओं को कतार में खड़े होने से छूट प्रदान करने के भी निर्देश है।

सभी मतदान केन्द्रों में 100 मीटर के भीतर मतदान सहायता केन्द्र बनाये गये है। मतदान दिवस को मतदान सहायता केन्द्र में मतदाताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यहां संबंधित क्षेत्र का बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) सहित अन्य कर्मचारी तैनात होंगे। मतदान सहायता केन्द्र में किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगा। मतदान सहायता केन्द्र में अतिरिक्त कुर्सियां एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ गर्भवती, शिशुवती, दिव्यांग तथा वरिष्ठजन मतदाताओं के आवश्यकतानुसार सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश है।

चुनाव प्रक्रिया में सेक्टर अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रुप में कार्य करेंगे। मतदान केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ मतदान दिवस में मतदान प्रतिशत की जानकारी उपलब्ध कराना एवं ईव्हीएम, वीवीपेट आदि की पर्याप्त जानकारी रखते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देने के निर्देश में भी जारी किए गए है।

विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए रायपुर जिले के सातों विधासभाओं में कुल 123 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। सर्वाधिक 26 प्रत्याशी रायपुर पश्चिम विधानसभा में है। धरसीवां एवं रायपुर ग्रामीण विधानसभा में 18-18, रायपुर उत्तर में 14, रायपुर दक्षिण में 23, आरंग में 11 और अभनपुर विधानसभा में 13 प्रत्याशी निर्वाचन मैदान में है।

लोरमी में त्रिकोणीय चक्रव्यूह में फंसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव

रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार लोरमी सीट हाई प्रोफाइल वीआईपी सीट बन गई है। इस बार इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी अरुण साव के सामने कांग्रेस प्रत्याशी थानेश्वर साहू हैं। वर्तमान में अरुण साव बिलासपुर सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस वजह से ये सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है। पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। क्योंकि सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी में ओबीसी वर्ग से अरुण साव सीएम पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। पूर्व सीएम रमन सिंह के बाद बीजेपी के सभी पोस्टर्स-बैनर में उनकी तस्वीरें प्रमुखता से दिख रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की रायगढ़ जिले के कोड़ातराई समेत कई सभाओं में वो पीएम के साथ रथ पर सवार दिखे, जबकि रमन सिंह मंच पर ही चुपचाप बैठे नजर आए। इसलिए लोरमी से साव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं थानेश्वर साहू सामाजिक वोटों के सहारे अपनी नैया पार करने की जुगत में लगे हुए हैं, जबकि सागर सिंह बैस के सामने अपने आप को साबित करने की चुनौती है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद साव छत्तीसगढ़ की राजनीति में तेजी से उभरे हैं। कांग्रेस ने साव को कड़ी

टक्कर देने के लिए उन्हीं के समाज (ओबीसी) से छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थानेश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया है। वहीं यहां पर चुनाव त्रिकोणीय होते दिख रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी (जेसीसीजे) ने सागर सिंह बैस को चुनाव मैदान में उतारा है और वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी, तो उन्होंने पार्टी छोड़कर जेसीसीजे का दामन थाम लिया।

अरुण साव ओबीसी वर्ग के साहू समाज से हैं। फिलहाल बीजेपी में ओबीसी वर्ग से कोई बड़ा कद का दिग्गज नेता नहीं है। ऐसे में यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो वे सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बहुल्य वाले क्षेत्र में जातिगत वोट काफी मायने रखते हैं। लोरमी विधानसभा में साहू समाज के वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इसलिए बीजेपी ने वर्ष 1993 से लेकर अब तक यानी 2023 तक लगातार सात बार इसी समाज से प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी की इस रणनीति को देखें तो सिर्फ दो प्रत्याशी मुनीराम साहू और तोखन साहू एक-एक बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के दर पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। दूसरी ओर सामान्य वर्ग से धरमजीत सिंह तीन बार कांग्रेस से और एक बार जेसीसीजे के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। वर्तमान में वो लोरमी से जेसीसीजे के विधायक हैं। फिलहाल वो बीजेपी में हैं।

2018 का परिणाम- विधानसभा चुनाव 2018 की बात करें, तो लोरमी में जेसीसीजे और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी ने लोरमी सीट पर जहां तोखन साहू को सियासी मैदान में उतारा था, तो वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी (जेसीसीजे) की ओर से धरमजीत सिंह चुनाव मैदान में थे। धरमजीत सिंह को 67 हजार से अधिक वोटों से जीत मिली थी। वहीं भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू को सिर्फ 42 हजार से अधिक वोटों से संतोष करना पड़ा था और उनकी हार हुई थी।

जातीय समीकरण- लोरमी में अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या करीब 52 हजार है। साहू समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 45 हजार है। कुर्मी समाज के भी मतदाता बड़ी संख्या में हैं। एसटी वर्ग के करीब 18 हजार मतदाता हैं। वहीं सामान्य वर्ग के करीब 45 हजार मतदाता हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सामाजिक वोटों के ध्रुवीकरण से प्रत्याशी बाजी मार सकते हैं। लोरमी के सियासत में इस बात की चर्चा है कि जो प्रत्याशी ओबीसी वर्ग के साथ ही सतनामी समाज का वोट हासिल करेगा, वही चुनाव में बाजी मारेगा।

लोरमी सीट का इतिहास- कांग्रेस के टिकट पर साल 2003 में धरमजीत सिंह जीते। कांग्रेस के टिकट पर साल 2008 धर्मजीत सिंह दोबारा विधायक बने। साल 2013 में बीजेपी के तोखन साहू ने बाजी मारी और विधायक बने। तीसरी बार जेसीसीजे के टिकट पर वर्ष 2018 में धर्मजीत सिंह जीते और विधायक बने।

स्थानीय मुद्दे- स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, कृषि, रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का आभाव।

कोटा में पहली बार जूदेव खिलाएंगे कमल या बरकरार रहेगा रेणु जोगी का जादू?

रायपुर। बिलासपुर जिले की कोटा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हर बार की तरह इस बार भी यह सीट वीआईपी हाई प्रोफाइल बनी हुई है। साल 2023 के चुनाव में कोटा से भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के सामने कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव हैं। यही से वर्तमान विधायक और जेसीसीजे के संस्थापक अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी भी चुनाव मैदान में हैं। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव बीजेपी के दिग्गज नेता रहे दिलीप सिंह जुदेव के बेटे हैं। इस वजह से कोटा में इस बार चुनावी घमासान है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कोटा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी यहां से कमल खिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। प्रबल प्रताप सिंह के सामने कोटा से कमल खिलाने की चुनौती है, तो रेणु जोगी के सामने चौथी बार इस सीट को बचाए रखने की जद्दोजहद है। वहीं अटल श्रीवास्तव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।

कोटा विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1965 को हुई थी। इस सीट से कांग्रेस जीतती आ रही है। यह छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी डॉ. रेणु जोगी की सीट हैं। आजादी के बाद जब से कोटा विधानसभा अस्तित्व में आया तब से यहां कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। इस रिकॉर्ड को पहली बार पिछले विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी से निकलीं रेणु जोगी ने तोड़ा और कोटा विधानसभा पर पहली बार किसी अन्य दल ने कब्जा किया।

बीजेपी ने इस बार कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को मौका दिया है ताकि चुनावी मुकाबला जोगी बनाम जूदेव रहे। हालांकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, लेकिन बीजेपी दो ध्रुवीय मुकाबले में कांग्रेस डैमेज करना चाहती है पर कांग्रेस की ताकत उसका इतिहास और उनके कैडर वोटर्स हैं।

2018 का परिणाम- विधानसभा चुनाव 2018 के परिणाम की बात करें, तो पिछली बार जेसीसीजे प्रत्याशी रेणु जोगी को सर्वाधिक 48,800 वोट मिले थे। वोटों का प्रतिशत 32.77 रहा। 45,774 वोट के साथ दूसरे नंबर पर बीजेपी के काशीराम साहू को संतोष करना पड़ा। कांग्रेस से 30,803 मतों के साथ विभोर सिंह तीसरे नंबर पर थे।

जातीय समीकरण- कोटा विधानसभा सीट पर कुल 2 लाख 11 हजार 166 वोटर्स हैं, जिनमें 1 लाख 5 हजार 281 पुरुष और 1 लाख 5 हजार 885 महिला मतदाता शामिल हैं। यह सीट आदिवासी बहुल्य है। 1 लाख 92 हजार 323 मतदाताओं में 65 फीसदी आबादी इसी वर्ग का है। इसके अलावा 25 फीसदी ईसाई मतदाता भी हैं। शहरी इलाकों में मुस्लिम, ब्राह्मण और दूसरी स्वर्ण जातियां भी चुनाव नतीजों को प्रभावित करती हैं। यहां ब्राह्मण, मुस्लिम, ईसाई और साहू जातियों की संख्या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। चुनाव में यही जाति हार-जीत तय करते हैं। इसलिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या

जेसीसीजे सभी यहां पर इन्हीं वर्ग पर फोकस रखकर विधानसभा में उतरते हैं।

कोटा विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। वर्ष 2018 का चुनाव छोड़ दें तो यहां पर ज्यादातर कांग्रेस जीतती रही है। बीजेपी यहां पर कमल खिलाने के लिए सियासी जंग लड़ रही है। साल 1952 से लेकर अब तक कोटा विधानसभा सीट पर 14 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। काशीराम तिवारी यहां पहले विधायक निर्वाचित हुए थे। उनके बाद मथुरा प्रसाद दुबे 4 बार और राजेंद्र शुक्ला 5 बार विधायक बने। शुक्ला के निधन के बाद साल 2006 में हुए उपचुनाव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतीं थी और तब से लगातार 2018 को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ही यहां जीतती रही है। साल 2018 कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी से रेणु जोगी चुनाव लड़ीं और विधायक बनीं। वह पहली महिला विधायक हैं जो पिछले तीन बार से जनप्रतिनिधि हैं। यहां की सियासी तासिर देखें तो रेणु जोगी को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर यहां से ब्राह्मण प्रत्याशी ही चुनाव जीतते रहे हैं।

स्थानीय मुद्दे- कोटा विधानसभा क्षेत्र में विकास की दर बहुत धीमी रही है। पुरानी विधानसभा सीट होने के बावजूद इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय के अलावा कई स्कूल और कॉलेज हैं। क्षेत्र के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं, जो कि 80 फीसदी आबादी की आय का मुख्य स्रोत है। क्षेत्र में कोयला खदान, पॉवर प्लांट और चावल मिल जैसे उद्योगों की मौजूदगी ने रोजगार के नए अवसर बनाएं है। इस क्षेत्र में अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट को सबसे पहले 6 जून 2012 को मंजूरी मिली थी, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। उस वक्त इसकी लागत लगभग 606 करोड़ थी, चार साल बाद जिसकी लागत लगभग 1,141 करोड़ हो गई। इस प्रोजेक्ट से लगभग एक लाख किसानों को पानी देने का दावा किया गया था। किसानों को यहां मिलने वाले मुआवजे और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को लेकर सरकार से बहस होती रहती है।

पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे। इसके तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित संभाग बस्तर की 12 सीटें और दुर्ग संभाग के नक्सल प्रभावित जिले राजनांदगांव, कवर्धा और खैरागढ़ की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। पहले चरण में कुल 78 प्रतिशत मतदान हुआ था। बस्तर की सभी 12 सहित कुल 16 सीटों पर पिछले चुनावें की तुलना में इस बार अधिक वोटिंग हुई है। वहीं 2018 की तुलना में 4 सीटों पर कम मतदान हुआ है। इन 4 सीटों में कबीरधाम जिला की दोनों सीट पंडरिया और कवर्धा के साथ खैरागढ़- छुईखदान जिला की खैरागढ़ सीट और राजनांदगांव जिला की खुज्जी सीट शामिल है। बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर इस बार रिकार्ड तोड़ वोटिंग हुई है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। इनमें 34 सीटें वीआईपी हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में से 10 सीटें वीआईपी थीं। कुल मिलाकर प्रदेश में 44 सीटें हाई प्रोफाइल हैं। इन सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसीजे के दिग्गज नेताओं के बीच मुकाबला होगा। भाजपा, कांग्रेस और जेसीसीजे के प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे।

100 प्रतिशत मतदान से जनप्रतिनिधि सुधरेंगे

प्रह्लाद सबनानी

भारत आज वैश्विक पटल पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है एवं भारत विश्व को कई क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में भी आ गया है। कुछ देश (चीन एवं पाकिस्तान सहित) भारत की इस उपलब्धि को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर समस्त विघटनकारी शक्तियां मिलकर भारत को तोड़ना चाहती हैं। इन विघटनकारी शक्तियों द्वारा भारत में जातीय संघर्ष खड़ा करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जबकि भारत के कई सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठन समस्त भारतीय समाज में एकजुटता बनाए रखना चाहते हैं ताकि भारत को एक बार पुन: विश्व गुरु बनाया जा सके। परंतु, आज विघटनकारी शक्तियों के निशाने पर मुखर रूप से हिंदुत्व, भारत एवं संघ आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों में राष्ट्रीयता का भाव विकसित किया है। संघ के स्वयंसेवक समाज की सज्जन शक्ति के साथ मिलकर समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार इन विघटनकारी शक्तियों को परास्त किया जा सकता है। भारत में शीघ्र ही निर्वाचन काल प्रारम्भ होने जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आज राष्ट्र को भारत माता के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले नागरिकों की बहुत अधिक आवश्यकता है। अत: भारतीय समाज द्वारा निर्वाचन में 100 प्रतिशत मतदान किया जाय एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत प्रत्याशी ही चुनाव जीत सकें, इसके लिए समाज को साथ लेकर भारतीय नागरिकों द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। इस संदर्भ में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा भी कई तरह के प्रयास समय समय पर किए जाते हैं ताकि देश के नागरिकों द्वारा 100 प्रतिशत मतदान किया जा सके। निश्चित ही 50 प्रतिशत नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की तुलना में 90 अथवा 100 प्रतिशत नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बेहतर प्रतिनिधि ही साबित होंगे। अत: अधिक से अधिक मतदान किया जाना आज समय की आवश्यकता है। इससे चुने गए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता में तो सुधार होगा ही साथ ही, वर्तमान समय में भारत की आर्थिक प्रगति भी जारी रह सकेगी एवं भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित होते हुए भी हम लोग देख सकेंगे। कई बार विभिन्न दलों के समस्त प्रत्याशी कुछ मतदाताओं को पसंद नहीं आते हैं, इन परिस्थितियों में ऐसे मतदाताओं को नोटा का बटन दबाने का अधिकार रहता है। परंतु, कोई प्रत्याशी मतदाता की नजर में 100 प्रतिशत खरा प्रत्याशी होगा, ऐसा सम्भव भी तो नहीं है। इन परिस्थितियों में कम से कम बुरे प्रत्याशी को चुना जा सकता है। नोटा का बटन दबाकर तो कम बुरे प्रत्याशी के स्थान अधिक बुरा प्रत्याशी ही चुना जा सकता है। संघ के परम पूज्य सर संघचालक भी कहते हैं कि नोटा में हम लोग सर्वोत्तम को भी किनारे कर देते हैं और इसका फायदा सबसे बुरा उम्मीदवार ले जाता है। होना यह चाहिए कि हमारे पास जो सर्वोत्तम उपलब्ध है, उसे चुन लें। प्रजातंत्र में सौ फीसदी लोग सही मिलेंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। यह आकलन पूर्णत: सही ही कहा जा सकता है क्योंकि मतदाता भले ही नोटा दबा कर यह समझे कि उसने सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया है लेकिन शायद उसे यह नहीं पता होता कि इस से किसी ऐसे उम्मीदवार की कम अंतर से हार हो सकती है जो उन सबमे सबसे बेहतर हो। ऐसे में नोटा को गए वोट अगर उस हारे उम्मीदवार को जाते तो वह जीत सकता था। अगर इस कारण किसी बुरे उम्मीदवार की जीत हो जाती है तो फिर नोटा दबाने के कोई मायने ही नहीं रह जाते। भारत में चुनावों पर हजारों करोड़ रुपए की राशि खर्च होती है। अत: केंद्र एवं राज्यों में मजबूत सरकारों का चुना जाना अति आवश्यक है, ताकि वे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को सफलता पूर्वक सम्पन्न कर सकें। यदि 100% मतदान के साथ किसी भी सरकार को चुना जाता है तो निश्चित ही मजबूत सरकार होगी एवं वह अपना कार्यकाल पूर्ण कर सकने में सफल भी होगी और इस प्रकार मध्यावधि चुनावों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

मतदाताओं की चुप्पी

सिद्धार्थ शंकर गौतम

एक दशक से भाजपा हर छोटा-बड़ा चुनाव जिस उत्सवधर्मिता से लड़ती दिखती है, कांग्रेस उसके पासंग भी नहीं है। यही कारण है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व एकजुटता से चुनावों में सक्रिय हो जाता है जबकि कांग्रेस में प्रादेशिक स्तर पर कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चलाने लगती है तथा आलाकमान देखो और इंतजार करो की स्थिति धारण कर लेता है।

कई पुराने दिग्गज भाजपाई जो पार्टी से बगावत कर चुके हैं उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे 36 भाजपायी अब पूर्व होकर या तो निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं अथवा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरूद्ध जनमानस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने 39 ऐसे साथियों को हाथ से झटक दिया है जो बागी हुए हैं। अंतर मात्र इतना है कि भाजपा के बागी 5 से 7 सीटों पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं जबकि कांग्रेस में इनकी संख्या 10-12 से अधिक हो गई है।

दिलचस्प यह है कि भाजपा के बागी को कांग्रेस पसंद कर रही है और कांग्रेस के बागी भाजपा के दुलारे बने बैठे हैं गोयाकि बागियों की दसों उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में है। हालांकि दोनों ही दलों के समक्ष एक यक्ष प्रश्न है कि क्षेत्र की एंटी-इनकंबेंसी को कैसे संभला जाए? कांग्रेस भी इस समस्या से दो-चार हो रही है क्योंकि ऐसी 30 विधानसभा सीटें हैं जहां हाथ को जनता का साथ दशकों से मिल रहा है। यहां एंटी-इनकंबेंसी का चेहरा दूसरा है।

मध्य प्रदेश में इन दिनों एक प्रश्न हर किसी की जुबान पर है कि किसकी सरकार बन रही है? किसे कितनी सीटें मिलेंगी? कौन जीत रहा है? अमूमन आम आदमी इसका उत्तर कांटे की टक्कर है में दे रहा है जबकि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर अपने दल की सरकार बनवा रहे हैं। हालांकि अंदरूनी तौर पर देखें तो कमोबेश हर प्रत्याशी की सांसें फूली हुई हैं क्योंकि इस बार मतदाता चुप है और 2018 में जब मतदाता ने चुप्पी साधी थी तो शिव का राज जाता रहा था। इस बार की चुप्पी पिछली बार की तुलना में अधिक रहस्यमयी है क्योंकि कोई भी खुलकर अपनी राय नहीं रख रहा।

मतदाता जितनी आत्मीयता से भाजपा प्रत्याशी का स्वागत कर रहा है उतने ही प्रेम से कांग्रेस प्रत्याशी को भी सम्मान दे रहा है। दोनों ही दलों के घोषणा-पत्र भी अमूमन समान ही हैं जिसके कारण चुप्पी बढ़ी है। ऐसे में प्रत्याशी का स्थानीय प्रभाव, मतदाताओं में उसकी पकड़, उसकी उपलब्धता जैसे फ़ैक्टर अहम हो गए हैं। चेहरे का प्रश्न बड़ा हो गया है और भाजपा का कार्यकर्ता केंद्रित चुनाव लड़ना उसके लिए कहीं न कहीं पेशानी का सबब बनता जा रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी मतदाताओं को दे रहे हैं। वे हर उस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं जहां भाजपा प्रत्याशी की स्थिति कमजोर है।

कांग्रेस भी मतदाता की चुप्पी से परेशान है क्योंकि कई सीटों पर जहां वह दशकों से काबिज है, मतदाता मूक दर्शक बना हुआ है। इस बार का मप्र विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक है क्योंकि तमाम चुनाव पूर्व सर्वे किसी के पक्ष में नहीं हैं। अलबत्ता सभी ने 50-60 सीटें ऐसी अवश्य बताई हैं जहां जीत-हार का अंतर 5000 से कम रहने वाला है। ऐसी स्थिति 2013 में 43 तथा 2018 में 46 सीटों पर बनी थी और तब भी मतदाता मौन था। 2018 में 10 सीटें तो ऐसी थीं जहां जीत-हार का अंतर 1000 वोट का था। वर्तमान में लगभग एक चौथाई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है और यहां मतदाता का मौन दोनों प्रमुख दलों पर भारी पड़ रहा है।

कांग्रेस का हर छोटा-बड़ा नेता अपनी सभा और रैलियों में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम पूछकर भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख रहा है और पार्टी है कि इस मामले में भ्रम की स्थिति बनाए हुए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस अंदाज में तूफानी तेजी से सभा और रैलियां कर रहे हैं, यह संकेत देता है कि यदि भाजपा जीती तो केंद्रीय नेतृत्व का उन्हें नकारना जनता हजम नहीं करेगी और 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका असर केंद्र के लिए सुखद नहीं होगा। किंतु जब-जब भाजपा सामूहिक नेतृत्व और कार्यकर्ता केंद्रित चुनाव लड़ने की अपनी बात पर आगे बढ़ती है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन का प्रश्न उसे कई कदम पीछे धकेल देता है।

गृहमंत्री अमित शाह ने चंचौड़ा-राजगढ़ की सभा में चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा शिवराज सिंह चौहान का नाम तो लिया किंतु इससे बड़े भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नरेंद्र सिंह तोमर पहले ही दिमनी विधानसभा में चतुकोणीय मुक़ाबले में घिरे हैं और अब उनके बड़े बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर उर्फ रामू भैया के करोड़ों के लेनदेन के कथित दो वीडियो वायरल होने से मामला उलझ गया है। जो भाजपा नेता छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे, वे मप्र में बचाव की भूमिका में आ गए हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव में उतरे नहीं हैं, फिर अमित शाह को उनका नाम लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह बड़ा प्रश्न है। दिग्विजय सिंह के गढ़ में सिंधिया का नाम लेकर क्या अमित शाह एक तीर से कई निशान साध रहे हैं? क्या वे राजा के सामने महाराजा को एक बार पुन: खड़ा करना चाहते हैं? क्या हिमंत विस्वा शर्मा के बाद भाजपा दूसरे मूल कांग्रेसी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना रही है? क्या शाह सिंधिया की राजनीतिक ताकत आंकना चाहते हैं? जनता और राजनीतिक विश्लेषक इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढने का प्रयास करेंगे किंतु चेहरे का प्रश्न क़यासों के चलते भाजपा कार्यकर्ता में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इतने पर भी भाजपा नेतृत्व मतदाताओं को भरोसा दे रहा है कि अंत भला तो सब भला।

कांग्रेस जनता को अपने संकल्प पत्र के वादों की याद दिलाते हुए उसे सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रही है किंतु सच यह है कि वह स्वयं भाजपा की 18 वर्षों की सरकार के विरूद्ध चल रही एंटी-इनकंबेंसी पर अधिक निर्भर है। प्रदेश में जमीन पर न के बराबर संघर्ष करने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी कमलनाथ युग में सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव लड़ने जा रही है और उसने भाजपा को यहां कड़ी टक्कर देते हुए अपना वर्चस्व दिखाया है।

वैसे भी इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए साख का विषय है क्योंकि 2018 में जीत के बाद भी कांग्रेस को डेढ़ साल के अंदर ही सत्ता गंवानी पड़ी थी। लिहाजा इस बार कमलनाथ फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं और 101 वादों के साथ जनता के समक्ष जा रहे हैं।

इसके अलावा जीत के बाद 2018 जैसी बगावत न हो, इसके लिए अधिकांश टिकट उन्होंने अपनों को दिए हैं। युवा वर्ग को साधने के साथ ही वे नेतृत्व के स्तर पर स्वयं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि उनकी राह में दिग्विजय सिंह चुनौती बनकर उभरे हैं। बेटों को स्थापित करने की जद्दोजहद में कांग्रेस का कितना नुकसान होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फ़िलहाल तो प्रदेश का मतदाता मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा और कांग्रेस के संकल्प के बीच बेहतर चुनने की मंशा से सभी विकल्पों को मौन रहकर तौल रहा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

यागकुण्डल्युपनिषद् (भाग-2)

गतांक से आगे...

(प्राणजय के लिए प्रमुख) आसन दो कहे गये हैं- पहला है पद्मासन, दूसरा है वज्रासन। दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा (ऊपर की ओर) करके रखने से सभी पापों का विनाश करने वाला पद्मासन होता है।

गर्दन, सिर एवं शरीर को एक सीध में रखकर बायें पैर की एड़ी को सीवन (योनि) स्थान में तथा दायें पैर की एड़ी उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा जाता है। [वैसे तो यह लक्षण सिद्धासन का है, परन्तु हठयोग प्रदीपिका जैसे ग्रन्थों में भी इसे वज्रासन कहा गया है; जबकि वर्तमान में दोनों घुटने मोड़कर दोनों एड़ियों पर बैठने की स्थिति वज्रासन कही जाती है।]

प्रमुख शक्ति कुण्डलिनी कही गई है, बुद्धिमान् साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भृकुटियों के मध्य ले जाता है, इसी क्रिया को शक्तिचालिनी कहते हैं। मुख्य रूप से कुण्डलिनी चलाने (जगाने) के दो साधन कहे गये हैं, सरस्वती चालन एवं प्राणरोध (प्राणायाम)। प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुण्डलिनी सीधी हो जाती है।

इस प्रकार पहले तुमको सरस्वती चालन के बारे में बताता हूँ। प्राचीन काल के विद्वान् इस सरस्वती को अरुंधती भी कहते थे। जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो, उस समय दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगाकर इसके (सरस्वती के) भली प्रकार संचालन करने से कुण्डलिनी स्वयं चलने (जाग्रत् होने लगती है फिर उस नाड़ी को द्वादश अंगुल लम्बे और चार अंगुल चौड़े अम्बर (वस्त्र) के टुकड़े से लपेटे।

[यहाँ कुण्डलिनी नाड़ी (कन्दस्थान) को 12 अंगुल लम्बे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटने का उल्लेख योग-साधना पद्धतियों के अनुकूल किया गया है। घेरंड संहिता तथा हठयोग प्रदीपिका (3.113) में इसी तरह की बात कही गई है। घेरंड संहिता में इतने स्थान पर श्वेत-कोमल वस्त्र लपेटकर पूरे शरीर में भस्म मलने की बात है और हठयोग प्रदीपिका में उस स्थान को उतने परिमाण से लिपटे वस्त्र जैसा कहा गया है।]

तब दृढ़तापूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अङ्गुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर अपनी (इच्छा) शक्ति से पहले बायें, फिर दायें नासिका के छिद्र से बार-बार रेचक और पूरक करे। इस तरह निर्भय होकर दो मुहूर्त (4 घटी- 96 मिनट) तक इसको चलाना चाहिए, साथ ही कुण्डलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित् मात्र ऊपर खींचे।

क्रमश: ...

लाला लाजपत राय

रेनू तिवारी

लाला लाजपत राय, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को जगराओं, लुधियाना जिले, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल और गुलाब देवी अग्रवाल के पुत्र थे। उनके पिता, जो उर्दू और फ़ारसी के शिक्षक थे, ने उनके उदार विचारों को प्रभावित किया, जबकि उनकी धार्मिक माँ ने उनमें मजबूत मूल्य पैदा किए। लाजपत राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के रेवारी स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राप्त की, जहाँ उनके पिता कार्यरत थे। 1880 में, लाजपत राय ने कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ वे लाला हंस राज और पंडित गुरु दत्त जैसे भावी स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आये। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदू सुधारवादी आंदोलन से प्रेरित होकर, वह आर्य समाज में शामिल हो गए और लाहौर में आर्य गजट के संस्थापक संपादक बन गए।

लाजपत राय का दृढ़ विश्वास था कि हिंदू धर्म भारतीय जीवन का आधार होना चाहिए, और वह राजनीति और पत्रकारिता के माध्यम से धर्म और भारतीय नीति में सुधार के लिए समर्पित थे। वह 1886 में हिसार चले गए, जहां उन्होंने कानून का अभ्यास शुरू किया और हिसार बार काउंसिल के संस्थापक सदस्य बने। छोटी उम्र से ही लाजपत राय में अपने देश की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी और 1886 में उन्होंने भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने का संकल्प लेते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिसार जिला शाखा की स्थापना की। उन्होंने हिसार से एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लिया।

1892 में, लाजपत राय लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष अभ्यास करने के लिए लाहौर चले गए और भारत की राजनीतिक नीति को आकार देने के लिए द ट्रिब्यून जैसे समाचार पत्रों में सक्रिय रूप से योगदान दिया। उन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो-वैदिक स्कूल की स्थापना का भी समर्थन किया। एक राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लाला लाजपत राय की यात्रा उनकी परवरिश, शिक्षा और राजनीति में प्रारंभिक भागीदारी के साथ शुरू हुई। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका समर्पण और समाज में उनका योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक श्रद्धेय नेता, लाजपत राय ने अपने समकालीनों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा और युवाओं की एक पीढ़ी को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अपने प्रभावशाली पत्रकारिता लेखन और विभिन्न आंदोलनों में अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, उन्होंने अपने समय के युवाओं में देशभक्ति और भक्ति की भावना जगाई।

लाला लाजपत राय के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कई महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना हुई। उन्होंने लाहौर में आर्य गजट की स्थापना की और हिसार कांग्रेस, हिसार आर्य समाज, हिसार बार काउंसिल और राष्ट्रीय डीएवी प्रबंध समिति जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, उन्होंने लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की और कराची में लक्ष्मी बिल्डिंग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज उनके सम्मान में एक पट्टिका के साथ खड़ी है।

1927 में, राय ने लाहौर में महिलाओं के लिए एक तपेदिक अस्पताल की स्थापना और प्रबंधन के लिए अपनी माँ के नाम पर एक ट्रस्ट की स्थापना की। गुलाब देवी चेस्ट अस्पताल, जिसका नाम उनकी मां के नाम पर रखा गया था, का उद्घाटन 17 जुलाई, 1934 को हुआ था। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को अंग्रेजों द्वारा क्रूर लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गंभीर चोटें आईं। अपनी गंभीर स्थिति के बावजूद, वह एक शक्तिशाली बयान के साथ भीड़ को संबोधित करने में कामयाब रहे, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि उन पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कीलें होंगे। दु:ख की बात है कि 17 नवंबर, 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सके थे।

चीन-भूटान की दोस्ती क्या गुल खिलाएगी

हर्ष वी पंत

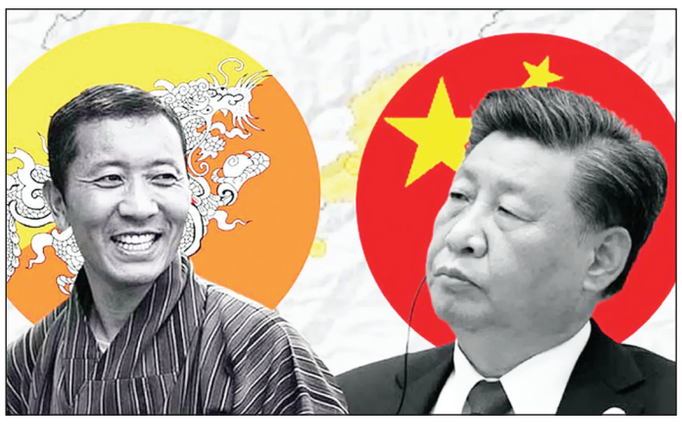

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हाल में (3 से 10 नवंबर) आठ दिनों की भारत यात्रा पर आए थे। इस यात्रा का मकसद भूटान और चीन के बीच संभावित सीमा समझौते से जुड़ी भारत की चिंताओं को कम करना था। पिछले महीने ही भूटान के विदेश मंत्री तांडी दोरजी चीन गए थे। उनकी चीन यात्रा ने दो वजहों से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। पहली, दोनों देश दशकों पुराने सीमा विवाद को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में एक सहयोग समझौता हुआ, जिसमें जॉइंट टेक्निकल टीम (जेटीटी) की जिम्मेदारियां और उसके संचालन के तरीके तय किए गए। सीमा से जुड़े मतभेदों को रेखांकित करने और उन पर सहमति बनाने का काम जेटीटी को ही सौंपा गया है। दूसरी, इस यात्रा से यह बात भी साफ हुई कि दोनों देशों के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं।

भारत ने इस पूरे प्रकरण पर सोची-समझी चुप्पी बनाए रखी है। यह इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह भूटान की स्थिति को समझता है और मौजूदा घटनाक्रम को अपने हितों के खिलाफ नहीं मानता। चीन के साथ भूटान का रिश्ता अगर अब तक आगे नहीं बढ़ा तो इसके पीछे बड़े देशों की पावर पॉलिटिक्स को लेकर भूटान की नापसंदगी रही है। पचास के दशक में तिब्बत पर चीन के कब्जा करने और फिर भूटान के आठ क्षेत्रों पर भी काबिज हो जाने के बाद उसकी यह अनिच्छा और बढ़ गई। नतीजा यह कि भूटान ने चीन से अपने कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर लिए, पी-5 देशों से कूटनीतिक संबंध बनाने में हिचकता रहा और भारत के साथ विशेष रिश्ता कायम कर लिया।

बहरहाल, चीन को इस छोटे से देश से अपने विवाद सुलझाने की जरूरत दो वजहों से आन पड़ी है। एक तो यह कि ऐसा करना एक एशियाई ताकत की उसकी हैसियत के लिहाज से अहम है। दूसरी बात यह कि इससे उसे भारत को लेकर अपनी आक्रामकता बढ़ाने में आसानी होगी। वैसे चीन और भूटान के बीच बातचीत काफी पहले से चलती रही है। दोनों देश 1988 में एमओयू साइन कर चुके हैं। 1998 में दोनों के बीच समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया। 2016 तक उनके बीच 24 राउंड की बातचीत हो गई थी। फिर भी विवाद को जल्द सुलझाने के लिए हाल के वर्षों में चीन न केवल भूटान के पूर्वी क्षेत्र के सकतेंग इलाके में नए दावे करने लगा बल्कि सीमा पर घुसपैठ और विवादित क्षेत्रों में बस्तियां बसाने को प्रोत्साहित करने लगा। नतीजा यह कि बिगड़ते भारत-चीन रिश्तों के दौर में भूटान उसके साथ संबंध सुधारने में लग गया। घरेलू मोर्चे पर इकॉनमी की चुनौतियां भी उसे इस ओर प्रेरित कर रही थीं। अतीत में भूटान चीन को अनदेखा कर सकता था, लेकिन अब उसके लिए चीन नई विश्व व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा हो गया है।

भूटान को चीन से होने वाला निर्यात जो 2020 में 2 अरब डॉलर हुआ करता था, 2022 में बढ़कर 15 अरब डॉलर हो गया। अवसर की कमी के चलते होने वाला युवाओं का पलायन ऐसा मसला है जिसकी वजह से भूटान सुधारों की राह पर चलना टाल नहीं सकता। इस लिहाज से भूटान को चीन रिफॉर्म और रिकवरी की राह पर अपना अभिन्न पार्टनर लगता है। भूटान को चीन से होने वाले आयात का स्वरूप ऐसा है- मसलन भारी मशीनें, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले उपकरण- जिससे साफ है कि समय के साथ चीन पर इसकी निर्भरता भी बढ़ेगी। यही वजह है कि भूटान ने हाल के वर्षों में चीन के साथ मतभेद मिटाने और कूटनीतिक रिश्ते शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। बावजूद इन सबके, भारत ने इस मामले में कोई सार्वजनिक बयान तक जारी नहीं किया। यह दर्शाता है कि भारत भूटान की सुरक्षा संबंधी और आर्थिक चिंताओं को समझता है और उसे इस देश के साथ अपने विशिष्ट रिश्तों पर भरोसा है।

भूटान से होने वाले कुल निर्यात का करीब 70 फीसदी भारत ही आयात करता है।

दोनों देशों के बीच का होने वाला व्यापार जो 2020 में 94 अरब डॉलर था, 2022 में बढ़कर 134 अरब डॉलर हो गया। यही नहीं, भारत ने भूटान की मौजूदा पंचवर्षीय योजना में 4500 करोड़ की सहायता की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच करीबी सुरक्षा सहयोग भी हैं। भारतीय सैन्य प्रशिक्षकों की टीम भूटानी सैनिकों को प्रशिक्षित करने का काम जारी रखे हुए है। 2007 के समझौते के मुताबिक दोनों देश एक-दूसरे के हितों का सम्मान करने को कानूनी तौर पर प्रतिबद्ध हैं। इन वजहों से माना जाता है कि चीन के साथ भूटान की बातचीत का भारत के साथ उसके करीबी संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

भले ही भूटान भारतीय हितों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे, भारत के लिए नए हालात में नई चुनौतियां सामने आना तय हैं। डोकलाम जैसे संवेदनशील विवादित मसले के रहते, सकतेंग क्षेत्र में उसके नए दावों को देखते हुए भारत यथास्थिति बदलने की चीन की क्षमता को लेकर स्वाभाविक ही सतर्क रहेगा। दूसरी बात यह कि चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के बाद भूटान भी उन एशियाई देशों में शामिल हो गया है, जहां अपने प्रभावों को लेकर चीन और भारत में रस्साकशी चलती रहती है। ध्यान रहे, चीन पहले ही संकेत दे चुका है कि भूटान के साथ कूटनीतिक रिश्ता बहाल होने के बाद आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। यही नहीं चीनी मीडिया भूटान की इस बात के लिए तारीफ कर रहा है कि वह चीन की तीन प्रमुख ग्लोबल इनीशटिव्स का समर्थन करता है। जाहिर है, चीन-भूटान रिश्तों का नया चरण भारत के लिए कुछ नए सवाल और मिले-जुले अर्थों वाले नए संकेत लेकर आ रहा है।

आज का इतिहास

2009 में आज ही के दिन टी. एस. ठाकुर को सुप्रीम कोर्स का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
2006 में 17 नवंबर के दिन ही अमेरिकी सीनेट ने भारत-अमेरिका परमाणु संधि को मंजूरी दी थी।
2005 में आज ही के दिन श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हुए थे।
1999 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को ने स्वीकृति दी थी।
1966 में 17 नवंबर के दिन ही भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था।
1933 में आज ही के दिन अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता देते हुए व्यापार के लिए सहमति दी थी।
1932 में 17 नवंबर के दिन ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी।
1869 में आज ही के दिन स्वेज नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया। यह नहर यूरोप को एशिया से जोड़ती है।
1869 में 17 नवंबर के दिन ही इंग्लैंड के जेम्स मूरी ने 13 हजार किलोमीटर लंबी पहली साइकिल रेस जीती थी।
1831 में आज ही के दिन इक्वाडोर और वेनेजुएला ग्रेटर कोलंबिया से अलग हुए थे।
1942 में आज ही के दिन अमरीकी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक मार्टिन स्कोर्सीस का जन्म हुआ था।
1900 में 17 नवंबर के दिन प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू का जन्म हुआ था।
2012 में आज ही के दिन भारतीय राजनेता और शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का निधन हुआ था।
1928 में 17 नवंबर के दिन ही स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन हुआ था।
1869 दस साल के निर्माण कार्य के बाद स्वेज नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया. यह नहर यूरोप को एशिया से जोड़ता है.
1928 स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार और पंजाबी लेखक लाला लाजपत राय शहीद हुए थे।
1997 दक्षिणी मिस्र में 68 विदेशी सैलानी तब मारे गए जब चरमपंथियों ने सैलानियों की बस पर हमला किया।

केंद्रीय राजनीति में प्रभावहीन दक्षिण की सियासत

आर. राजगोपालन

यदि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव और दक्षिण भारतीय राजनीति का गहन विश्लेषण किया जाए, तो दो तथ्य सामने आते हैं। पहला, दक्षिण भारत के छह राज्यों में लोकसभा चुनाव के नतीजे केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए प्रमुख कारक नहीं बनेंगे। दूसरा, इन छह राज्यों में लोकसभा चुनाव का नतीजा मिला-जुला और विभाजित रहेगा।

वर्ष 2019 से दक्षिण भारत के इन छह राज्यों में कई नए चेहरे उभरकर आए हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आध्यात्मिक एवं सिनेमा जगत का प्रभाव राजनीति पर रहा है। आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण और तमिलनाडु के जोसेफ विजय राजनीति के नए चेहरे हैं, जो सिनेमा की पृष्ठभूमि से आए हैं। दक्षिणी राज्यों की राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है। इन छह राज्यों में लोकसभा चुनाव का नतीजा बंटा हुआ हो सकता है। बेशक राज्य स्तरीय दलों का कहना है कि दक्षिण की राजनीति में क्षेत्रीय क्षत्रप हावी हैं, लेकिन कांग्रेस या भाजपा का पूरी तरह सूपड़ा साफ नहीं होगा। तमिलनाडु एवं कर्नाटक को छोड़ दें तो, दक्षिण भारत के छह राज्यों में से बाकी चार राज्य एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दोनों तेलुगू भाषी राज्य हैं, लेकिन तेलंगाना काफी आक्रामक है। पुदुचेरी और केरल की राजनीति भी अपनी तरह से चरम पर है।

आइए, सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। इस राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा आश्चर्य होने वाला है। द्रविड़ राजनीति तेजी से खत्म हो रही है और यह तमिलनाडु के 2024 के नतीजों में दिख सकता है। तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में पहली बार तीन नए चेहरे 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के विजेता का भाग्य तय करेंगे। द्रमुक और अन्नाद्रमुक के अलावा ये तीन नए चेहरे कौन हैं? भाजपा नेता के अन्नामलाई, नाम तमिलर काची के नेता और पूर्व अभिनेता सीमन और तीसरे हैं सिनेमा जगत के मिनी सुपरस्टार जोसेफ विजय। ये तीनों चेहरे पहली या दूसरी बार के मतदाताओं को रिझाएंगे। ये तीनों द्रविड़ पार्टियों से 25 से 30 फीसदी वोट छीन सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अगर इसमें सफल नहीं भी रहे, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में तो निश्चित ही ये ऐसा करने वाले हैं।

तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता जैसी कद्दावर शख्सियतों की कमी महसूस की जा रही है। यह स्थान कौन भरेगा? क्या नरेंद्र मोदी या भाजपा के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाला कोई व्यक्ति या राहुल गांधी के समर्थन से मल्लिकार्जुन खरगे। यह ठीक है कि राजग से अन्नाद्रमुक के

बाहर निकलने के बाद अन्नाद्रमुक द्वारा कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव दिया जा रहा है, लेकिन गठबंधन में पार्टी बदलने का इतना अहम फैसला संभव नहीं है। इसके लिए दिसंबर के पहले हफ्ते में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन दिसंबर, 2023 से फरवरी, 2024 के बीच मात्र तीन महीने का समय रहता है, इसलिए गठबंधन में छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश का राजनीतिक संघर्ष भी दिलचस्प है, जहां जगन रेड्डी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करने का उनका राजनीतिक निर्णय और समय इतना सही था कि जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभरी। तेलुगू देशम पार्टी के नेता नायडू ने मोदी से माफी मांगने के बजाय मोदी और भाजपा के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया। आंध्र प्रदेश की राजनीति का भविष्य दो चेहरों के बीच बंटा हुआ है-एक हैं नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। जाहिर है, जगन रेड्डी राज्य की राजनीति के केंद्र में हैं। कांग्रेस वहां कोई ताकत नहीं है, क्योंकि उसने एक दशक पहले राज्य को दो भागों में बांट दिया था। तेलंगाना में कांग्रेस की पकड़ है, लेकिन उसकी जगह को हड़पने की कोशिश में भाजपा लगी हुई है। बीआरएस के कद्दावर नेता को परास्त करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेता लगातार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं।

केरल में माकपा एक प्रमुख ताकत है। लेकिन मुख्यमंत्री विजयन अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस से कैसे निपटेंगे? माकपा और वाम मोर्चा केरल में कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। माकपा के दिग्गज नेता अच्युतानंदन ने कहा कि राहुल गांधी को माकपा 2024 के चुनाव में हरा देगी। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कट्टर कांग्रेसी नेता माकपा की ओर रुख कर रहे हैं। इन सबके बीच क्या भाजपा के लिए 2024 में कोई जगह बनेगी ? इस सवाल का जवाब संदिग्ध है।

कर्नाटक कांग्रेस के लिए अहम राज्य है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर पाएंगे। जोरदार तरीके से इसका उत्तर 'नहीं' है। पार्टी के भीतर ही मुख्यमंत्री के कट्टर दुश्मन मौजूद हैं। राज्य कांग्रेस के चार गुट हैं, जो लोकसभा चुनाव से पहले सिद्धारमैया को अपदस्थ करना चाहते हैं। कर्नाटक में खरगे और गांधी परिवार की परीक्षा होने वाली है। जनता दल (एस) ने बेहद चतुराई से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा से गठबंधन कर लिया है। जनता दल (एस) की ओर से कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिशें हो रही हैं। चाहे जिस भी तरीके से आप देखें, कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें नई दिल्ली में सरकार गठन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस से मतदाताओं की निराशा के कारण भाजपा को अधिक फायदा मिलना तय है।

संक्षेप में कहें तो, या तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की बंटी हुई राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगले एक दशक में भाजपा दक्षिण भारत के चार प्रमुख राज्यों-तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपनी मजबूत पकड़ बनाने का दावा कर सकती है। पहली बार के मतदाता, जो 2002 में पैदा होने के बाद से नरेंद्र मोदी युग में जी रहे हैं, उन्होंने डिजिटल क्रांति देखी है। वर्ष 2024 का फैसला डिजिटल युवाओं के वोट बैंक, खासकर महिलाओं के वोट बैंक द्वारा होने वाला है।

राजस्थान में दोनों पार्टियों के लिए बहुमत पाना एक चुनौती

सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी

अब जब चुनाव में नाम वापसी की तिथि जा चुकी है और शेष बचे उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह भी मिल गए हैं, राजस्थान में चुनाव की स्थिति साफ होने लगी है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि आगामी 25 नवंबर को होने वाले चुनाव आर पार के चुनाव नहीं हैं, यह बहुत फंसा हुआ चुनाव है और उंट किसी भी करवट बैठ सकता है। भाजपा का पूर्ण बहुमत का दावा जमीन पर उतना प्रभावी नहीं दिख रहा है, जितना किया जा रहा है और कांग्रेस की वापसी भी उतनी आसान नहीं लग रही है, जितनी मेहनत अशोक गहलोत कर रहे हैं। बीते वर्षों में हुए चुनाव किसी ना किसी मुद्दे पर केन्द्रित रहे हैं, लेकिन यह चुनाव ऐसा अनोखा चुनाव है, जिसमें कोई भी मुद्दा

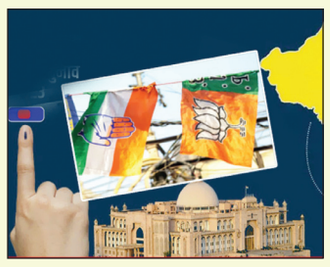

जनमानस के बीच में नहीं है। ना अशोक गहलोत की मुफ़्त योजनाएं मतदाताओं को लुभा रही हैं, ना ही भाजपा का सामूहिक नेतृत्व मतदाताओं को समझ आ रहा है। तो कुल मिलाकर यह चुनाव मुद्दों और पार्टियों की बजाय अच्छे और सच्चे उम्मीदवारों के चयन का चुनाव है। कोई भी उम्मीदवार सिर्फ पार्टी का समर्थन मिलने मात्र से विजय के निकट पहुंच गया है, यह कहना अब बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग के तहत अपने सात सांसदों योगी बालकनाथ, दीया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड, नरेन्द्र खींचड़, डा किरोडी लाल मीणा, देवजी पटेल और भागीरथ चौधरी को विधानसभा चुनाव में उतारा लेकिन स्थिति यह है कि एकमात्र दीया कुमारी और नरेन्द्र खींचड़ को छोड़कर बाकी सांसदों को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा और अभी भी स्थिति सहज नहीं हुई है। पहली बार देखने में आया है कि नामांकन से पहले उम्मीदवारों के समर्थन में हजारों लोगों का रैला उनके समर्थन में उमड़ा। ऐसा लगने लगा कि उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव सिर्फ औपचारिकता है, जनता ने अपना विधायक पहले से ही चुन रखा है लेकिन प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार ने भी उतना ही जनसमर्थन दिखा कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। इन चुनावों में कोई विकास, हिन्दुत्व या राष्ट्रीय मुद्धों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जातियां और स्थानीय समीकरण ही चुनाव का भविष्य तय करने वाले हैं। इस चुनाव का रोचक तथ्य यह है कि यह चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यह अवसर प्रदान कर रहा है कि वे अपनी पार्टी के नेताओं को बता सकें कि पार्टी के नेताओं की पसंद और कार्यकर्ताओं की पसंद के बीच कितना फासला बढ़ गया है, पार्टियां अपनी प्राथमिकताओं और पसंद के आधार पर टिकिट तो किसी को भी दे सकती हैं, लेकिन कार्यकर्ता उसे स्वीकार ही करेंगें यह आवश्यक नहीं। इस बात का अनकहा उदघोष यह भी है कि कार्यकर्ता अब अनुशासन के डंडे से भयमुक्त हो चुका है। प्रत्याशियों के नामांकन मे उमड़ रही भीड़ इन चुनावों को रोमांचक कर रही है। इन जनसमूहों को देखकर यह कहना मुश्किल है कि जिस उम्मीदवार के पक्ष में लोग जुट रहे हैं वो उसके मतदाता ही हैं। यदि इस भीड़ को उम्मीदवार की जीत का पैमाना मानें तो ऐसा संदेश आ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल 101 का जादुई अंक नहीं छू पायेंगें और सरकार बनाने की चाबी निर्दलियों और छोटी पार्टियों के पास रहेगी। हालांकि चुनाव से पहले गहलोत यह कहते रहते थे कि जनता में उनके प्रति नाराजगी नहीं है, बल्कि उनके विधायकों के प्रति है। लेकिन वे भी अपने ज्यादातर विधायकों को फिर से टिकट देने के लिए बाध्य हुए। यही हाल भाजपा का रहा, ना जाने कितने ही सर्वे भाजपा ने अलग अलग स्तर पर कराये, लेकिन जिनको उम्मीदवार बनाया उनके बारे में चर्चा तक नहीं थी, सर्वे में नाम आने की बात तो बहुत दूर रह जाती है। यही एक मात्र कारण है कि भाजपा में तो कम से कम कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच में गहरी खाई दिख रही है। भाजपा उसको कितना पाट पायेगी, यह तो समय ही बता पायेगा। भाजपा इस अंतर को जितना कम करेगी, उतना ही वो सरकार बनाने के निकट पहुंचेगी।

बीआरएस-कांग्रेस की जंग में भाजपा को मौन लाभार्थियों से उम्मीद

गुलाम अहमद

तेलंगाना के विधानसभा चुनाव नए तरह का समीकरण गढ़ते दिख रहे हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई गई है। कुछ इलाकों में कांग्रेस को बीआरएस पर बढ़त ही बताई गई है। हालांकि बीआरएस के खिलाफ 9 साल की एंटी इन्कंबेंसी के बावजूद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की कई लोकप्रिय योजनाओं के असर को नजरंदाज करना आसान नहीं होगा। बीआरएस और कांग्रेस के सबसे मजबूत होने के बावजूद भाजपा को केंद्रीय योजनाओं के मौन लाभार्थियों से बड़ी उम्मीद है। राज्य में 30 नवंबर को मतदान होना है। तेलंगाना के चुनावी रण किसी भी लिहाज से कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि विधानसभा चुनावों में बीआरएस और कांग्रेस के प्रदर्शन से अगले लोकसभा चुनाव की तस्वीर तय हो सकती है। वैसे तो तेलंगाना में पिछले दो चुनावों से कांग्रेस यहां मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन पिछले कई साल से भाजपा ही सड़कों पर विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाते ज्यादा नजर आती रही है। कांग्रेस की बात करें तो इसके पक्ष में हाल में कर्नाटक में मिली बड़ी जीत का उत्साह शामिल है। पार्टी को लगता है कि बीआरएस सरकार के खिलाफ 9 वर्ष की एंटी-इन्कंबेंसी के साथ उसकी 6 चुनावी गारंटियां जीत दिला सकती हैं। तेलंगाना कर्नाटक का पड़ोसी राज्य है और कर्नाटक चुनाव में गारंटियों के बूते कांग्रेस को मिली सफलता का असर यहां भी पड़ने की संभावना से जानकार इनकार नहीं कर रहे है। इसके अलावा, 2014 और 2018 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो पता चलता है, हालांकि बीआरएस ने दोनों बार प्रभावशाली सफलता हासिल की थी लेकिन कांग्रेस के वोट शेयर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस तेलंगाना राज्य बनाने के श्रेय का दावा भी करती है। अपने जमीनी संगठन के बूते कांग्रेस को लगता है कि वह वोटरों तक यह बात सफलतापूर्वक पहुंचा सकती है। अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद कांग्रेस के लिए भाजपा से जुड़ी कई अहम बातों को नजरंदाज करना भारी पड़ सकता है। राज्य में हुए उपचुनावों और हैदराबाद निगम चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस से काफी बेहतर रहा है। कांग्रेस गारंटियों की बात करती है, तो केंद्र सरकार की विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं ने भाजपा के पक्ष में लाभार्थियों का एक मौन वोट बैंक तैयार किया है। भाजपा ने राज्य में आदिवासियों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर 10 फीसदी करने का वादा किया है। राज्य सरकार के अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या 9 फीसदी से ज्यादा है।

राज्यपालों पर सुप्रीमकोर्ट की सख्ती की वजह

अजय सेतिया

तमिलनाडु के अनुभवहीन अक्खड़ राज्यपाल आर.एन. रवि के मुकाबले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित सुलझे हुए राजनीतिज्ञ रहे हैं। यह कोई पहला मौक़ा नहीं है, जब सुप्रीमकोर्ट से राज्यपालों को फटकार पड़ रही है। केंद्र में कांग्रेस सरकारों के समय बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी भी इसी तरह की डांट खा चुके हैं। उससे भी थोड़ा पीछे जाएं तो आंध्र प्रदेश में चुनी हुई एन.टी. रामाराव की सरकार को बर्खास्त करने के लिए ठाकुर राम लाल को बाद में इस्तीफा देना पड़ा था।

नब्बे के दशक में गोवा के राज्यपाल भानु प्रताप सिंह ने अपनी मर्जी से एक मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके एक मंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। बाद में उन्हें खुद राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राज्यपालों की मनमानियों के किस्से भरे पड़े हैं। कुछ राज्यपालों की मनमानियों के मामले सुप्रीमकोर्ट में जाते हैं, और कुछ के सिर्फ राजनीतिक विवाद बन कर रह जाते हैं।

अक्सर ऐसा होता है कि राज्यपालों का उन्हीं मुख्यमंत्रियों के साथ विवाद होता है, जहां केंद्र सरकार की विरोधी पार्टी की सरकार होती है। पंजाब, तमिलनाडु, बंगाल और केरल हाल ही के विवादों के ताज़ा उदाहरण हैं। इन सभी राज्यों के राज्यपालों के मामले सुप्रीमकोर्ट में लंबित हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में सीपीएम की सरकारे हैं, ये चारों ही राजनीतिक दल भाजपा विरोधी और इंडी एलायंस का हिस्सा हैं।

हाल ही में सुप्रीमकोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बारे में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप को पता है कि आग से खेल रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होते, इसलिए उन्हें चुनी हुई सरकारों

के कामों में अड़चन नहीं डालनी चाहिए। पंजाब में लंबे समय से राज्यपाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्यपाल की ओर से भेजे गए किसी भी पत्र का जवाब नहीं दे रहे थे, इस पर राज्यपाल पुरोहित ने राज्य सरकार को एक धमकी भरा पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था कि राज्य सरकार उनके पत्रों का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए उन्हें मजबूर हो कर राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ेगा कि पंजाब में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार का आरोप है कि राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे है। ठीक इसी तरह का विवाद बहुत लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच चलता रहा।अब कुछ उसी तरह का विवाद तमिलनाडु सरकार और वहां के पुलिस पृष्ठभूमि के राज्यपाल आर.रन. रवि के बीच चल रहा है।

2014 के बाद यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने किसी राज्यपाल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की हो। पहले भी कई राज्यपालों की भूमिका पर कोर्ट सवाल उठा चुकी है, तो कईयों को फटकार लगा चुकी है। 2016 में जब उत्तराखंड के राज्यपाल के.के. पॉल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ ने एक अवांछित टिप्पणी भी की थी कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट नहीं हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य में सरकार रहेगी या नहीं, यह फैसला सिर्फ विधानसभा में हो सकता है। कोर्ट ने विधानसभा में मत विभाजन का निर्देश दिया, जहां विधानसभा में कांग्रेस बहुमत हासिल करने में सफल रही।

2016 में पूर्व आईएएस अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई जब उन्होंने बहुमत होते हुए भी कांग्रेस सरकार को अपदस्थ कर दिया था। राज्यपाल जेपी राजखोवा ने पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी और फिर कांग्रेस के ही एक बागी को मुख्यमंत्री बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने राज्यपाल जेपी राजखोवा को बर्खास्त कर दिया था।

इस समय तमिलनाडु, केरल, पंजाब, बंगाल और तेलंगाना के राज्यपालों के मामलों पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन सभी राज्यों की सरकारों ने अपने राज्यपालों की मनमानी की शिकायत की है। राज्यों का कहना है कि राज्यपाल संविधान के तहत काम नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के बाद राज्यपाल की भूमिका पर बड़े पैमाने पर सुनवाई करने की बात कही है।

देश में अभी 14 राज्यों में उन पार्टियों की सरकार है, जो केंद्र की सत्ता में शामिल नहीं है। इनमें 11 राज्य सरकारें भाजपा विरोधी इंडी एलायंस का हिस्सा हैं। यही टकराव का बड़ा कारण है। इसमें कोई शक नहीं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद विशुद्ध रूप से राजनीतिक होता है। इनकी नियुक्ति भी राजनीतिक आधार पर होती है। लेकिन देखा यह गया है कि अगर राज्यपाल अनुभवी और सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ है तो विवाद को ज्यादा लंबा नहीं खींचने देता, लेकिन अगर उसकी पृष्ठभूमि पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी की हो, तो वे घमंड के घोड़े पर सवार होते हैं। मोदी राज में के.के. पॉल और आर.एन. रवि इसके दो प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

दिल्ली में सियासी उथल-पुथल की आशंका

आदिति फडणीस

अपनी आत्मकथा में लालू प्रसाद ने चारा घोटाले में अपनी गिरफ्तारी के घटनाक्रम का जिक्र किया है। यह बात जुलाई 1997 की है जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने घोषणा की थी कि उसके पास उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दी।

कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने यह सुझाव दिया कि उनकी जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। राज्यपाल एआर किदवई ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में किसी की जरूरत है क्योंकि अगर अदालत जमानत देने से इनकार करती है और उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश देती है तब लालू के लिए काम करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। उन्होंने अपनी जीवनी के लेखक को बताया, 'तकनीकी रूप से, मुझे इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन मैंने मानदंड तय करते हुए पद छोड़ने का फैसला किया।' सितंबर 2014 में भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल भेज दिया गया था। रविवार का दिन था।

उन्होंने अपनी परिवहन मंत्री सेंतिल बालाजी सहित अपनी पार्टी के कुछ सहयोगियों को जेल में नाश्ते पर बैठक के लिए बुलाया और उनसे विधायक दल का नया नेता चुनने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने अपनी पसंद के हिसाब से ओ पनीरसेल्वम का नाम लिया जो उस बैठक में मौजूद थे। अब दिल्ली के हाल के घटनाक्रम पर विचार करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि उनके समर्थक कहें कि वह जेल से भी दिल्ली सरकार चलाएंगे और चला सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली आबकारी घोटाले में उन्हें तलब किए जाने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपने सहयोगियों की बैठक बुलाई जिन्होंने उनसे कहा कि उन्हें पद नहीं छोड़ना चाहिए और इस तरह किसी उत्तराधिकारी का नाम तय करने की बात भी लगभग अप्रासंगिक हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, 'हम जेल में कैबिनेट की बैठक करने के लिए अदालत की अनुमति लेंगे।'

केजरीवाल ने ईडी को पहले ही पत्र लिखकर कहा था कि वह पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश की यात्रा की। अपने भाषण में उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब मैं जेल में रहूंगा या बाहर रहूंगा। आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन आप केजरीवाल के विचारों को कैसे रोक सकते हैं?' हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ऐसा करने में काफी दिलचस्पी ले रहा है और अगर ऐसा होता है तब उपराज्यपाल वी के सक्सेना को विधानसभा की बैठक बुलाने, सदन का नया नेता चुनने का निर्देश देने में बहुत कम समय लगेगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है तब विधानसभा भंग की जा सकती है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी है और यहां बिना मुख्यमंत्री के काम नहीं चल सकता है।

संभव है कि आम आदमी पार्टी भी यह फैसला करे

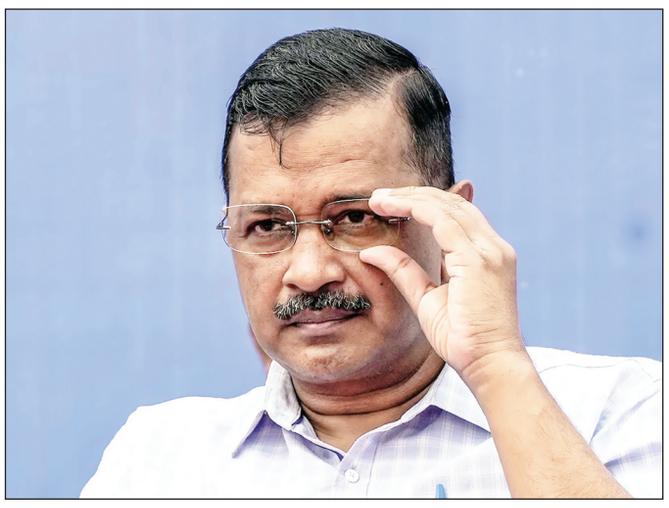

कि सोच-समझ कर एक उत्तराधिकारी 'नामित' कर दिया जाए। यह नाम आतिशी का भी हो सकता है जो कई मंत्रियों के जेल में बंद होने के बाद से मंत्री के रूप में कई काम संभाल रही हैं। इसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का नाम भी हो सकता है जिनका नाम आप के अहम नेताओं में शामिल है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का नाम भी संभावित विकल्पों में हो सकता था लेकिन वे दोनों पहले से ही जेल में हैं। अगर केजरीवाल जेल चले भी जाते हैं तो इस बात की संभावना नहीं है कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में अखिल भारतीय स्तर पर कोई बड़े विद्रोह जैसी स्थिति बनेगी। ऐसे कई अधिकारी हैं जो पार्टी के इस हश्र पर दुखी नहीं होंगे क्योंकि पार्टी का रुख अफसरशाहों के प्रति बहुत तालमेल वाला नहीं बताया जाता है।

हालांकि एक बार मामला पूरा हो जाने के बाद इसमें शायद ही कोई संदेह है कि केजरीवाल चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे और वह दिल्ली के दिल को फिर से जीतने में सक्षम होंगे। यही बात भाजपा को परेशान कर रही है और बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि उसने एक राज्य, आप के चलते गंवा दिया बल्कि पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में भी 13 प्रतिशत वोट मिले। गुजरात में इतना वोट दिग्गज भाजपा नेता केशुभाई पटेल भी तब हासिल नहीं कर पाए थे जब उन्होंने भाजपा से बगावत करते हुए अपनी पार्टी बनाई थी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लगातार मजबूत होती जा रही है और पिछले साल इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। केजरीवाल ने इस सफर को 'अकल्पनीय' बताया। उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि कल ही साढ़े 10 साल पहले हमने अपनी पार्टी बनाई थी। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि पार्टी को एक विधायक मिलेगा और आज, 10 वर्षों में आप एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है।' दिल्ली के मतदाताओं के एक वर्ग के बीच 'आप' की लोकप्रियता के बारे में कोई संदेह नहीं है। पूर्वी विनोद नगर के एक सरकारी स्कूल में जर्मन और स्पेनिश जैसी भाषा सीखने के विकल्पों के साथ, दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच पढ़ाई जाती है।

मोहल्ला क्लीनिक की बात करें तो उनमें से कुछ काम नहीं करते लेकिन कई अच्छी तरह संचालित हो रहे हैं। वातानुकूलित सार्वजनिक बसें महिलाओं और बच्चों से भरी हुई हैं जिसमें उनका कोई किराया नहीं लगता है। हालांकि आम आदमी पार्टी को कई वैचारिक मुद्दों पर बराबर ही दोषी माना जाना चाहिए। इसके एक मंत्री ने रामायण के सुंदर कांड का पाठ कराने का आदेश दिया जो हर हफ्ते संभवत: सरकारी खर्च पर होना था। पार्टी बुजुर्गों को तीर्थस्थान की यात्रा भी काफी रियायती दरों पर कराने की योजना जारी रख रही है।

लेकिन पार्टी ने मतदाताओं को यह समझाने की जरा भी जहमत नहीं उठाई कि वह बिलकिस बानो के बलात्कार के दोषियों की सजा माफी में गुजरात सरकार की भूमिका को किस तरह देखती है। हालांकि आप के नेता गोपाल इटालिया ने कहा कि यह कदम निंदनीय है लेकिन मनीष सिसोदिया ने इस पर जोर न देते हुए कहा कि पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर ज्यादा चिंतित है। दिल्ली में भाजपा नेताओं का कहना है कि वे चाहते हैं कि केजरीवाल को लंबे समय तक परिदृश्य से दूर रखा जाए। हालांकि यह समझना बेहद मुश्किल है कि जो पार्टी एमसीडी चुनाव हार गई हो वह इस स्थिति का फायदा किस तरह उठाएगी। कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। इन हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में एक और कोहरा छाने वाला है। हालांकि अभी इसका इंतजार करना होगा।

छग विस चुनाव के दूसरे चरण में 17 नवंबर को एक करोड़ 63 लाख वोटर्स करेंगे मतदान

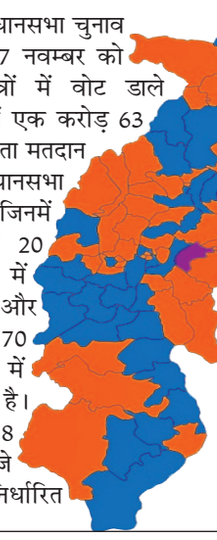

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 नवम्बर को 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में एक करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें है, जिनमें से पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुका है और दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने वाला है। इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

आपको बताते चलें कि केवल एक विधानसभा क्षेत्र बिन्द्रानवागढ़ के 9 मतदान केंद्रों कामरभौदी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीनकछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा बिन्द्रानवागढ़ के शेष मतदान केंद्रों में अन्य 69 विधानसभा क्षेत्रों की तरह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में मतदान वाले 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में राज्य के कुल एक करोड़ 63 लाख 14 हजार 479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 81 लाख 41 हजार 624 पुरुष मतदाता, 81 लाख 72 हजार 171 महिला मतदाता तथा 684 तृतीय जेंडर मतदाता शामिल हैं।

दूसरे चरण में इन 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा मतदान

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में भरतपुर-सोनहट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़ मतदान किया जाएगा। इसके अलावा सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी-बालोद, डौंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान होगा। दोनों चरणों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी।

छग विस चुनाव में डुप्लीकेट का खेल

एक ही नाम के प्रत्याशी से मदाताओं की बढ़ी उलझन

छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान के लिए 17 दिसंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस-भाजपा समेत सभी राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस बीच 70 सीटों में से 25 प्रतिशत सीटों पर हमनाम प्रत्याशी (एक जैसे नाम) होने के कारण राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारकों को प्रत्याशी की जगह चुनाव चिन्ह के प्रचार पर जोर देना पड़ रहा है। कुछ जगह पर जानबूझकर भी हमनाम प्रत्याशियों को उतारा गया है। इसके पहले भी हमनाम पालिटिक्स में राष्ट्रीय फंसती रहीं है।

रायपुर संभाग में कसडोल विधानसभा सीट

कसडोल विधानसभा सीट पर कांग्रेस-भाजपा दोनों ही प्रत्याशियों के खिलाफ हमनाम प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां कांग्रेस ने संदीप साहू को टिकट दी है। संदीप साहू के नाम से एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से धनीराम धीवर चुनावी मैदान में हैं। उनके भी हमनाम धनीराम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।

सरगुजा संभाग की प्रेमनगर विधानसभा सीट

सरगुजा संभाग में कुल 14 सीटे हैं। यहां प्रेमनगर सीट पर कांग्रेस-भाजपा दोनों ही दलों के अधिकृत प्रत्याशी के हमनाम भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार एक-दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के नाम को लेकर मतदाताओं को उलझन में डालने के लिए इस तरह राजनीति की जा रही है। प्रेमनगर सीट पर में कांग्रेस के प्रत्याशी खेलसाय सिंह मैदान में हैं। इसी नाम से एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी भूलन सिंह मरावी के नाम से ही भी एक निर्दलीय प्रत्याशी भूलन सिंह चुनावी मैदान में हैं।

बिलासपुर संभाग में तीन-तीन व्यास

बिलासपुर संभाग की जांजगीर-चांपा सीट से कांग्रेस ने व्यास कश्यप को टिकट दिया है। इस सीट पर तीन अन्य निर्दलीय व्यास कश्यप चुनावी मैदान में हैं। यहां भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल चुनाव लड़ रहे हैं।

अमरजीत भगत के सामने तीन-तीन रामकुमार

सरगुजा संभाग की सीतापुर सीट पर कांग्रेस की ओर से मंत्री अमरजीत भगत चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भाजपा ने पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो को चुनावी मैदान में उतारा है। रामकुमार के नाम से ही यहां दो अन्य निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। इस तरह इस सीट पर तीन-तीन रामकुमार चुनावी मैदान में उतर आए हैं।

पूर्व मंत्री अमर और मंत्री डहरिया के भी हमनाम

बिलासपुर सीट पर भाजपा से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से शैलेष पांडेय टक्कर दे रहे हैं। इस सी पर परिवर्तन पार्टी आफ इंडिया से अमर रूपानी चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह रायपुर संभाग के आरंग में मंत्री डा. शिवडहरिया के चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी शिवकुमार मैदान में हैं।

यहां निर्दलियों के भी हमनाम

रायपुर के धरसींवा विधानसभा सीट पर रवि कुमार, रविदास चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह कोटा सीट से दो मनोज कुमार लड़ रहे हैं। जशपुर सीट से दो प्रदीप चुनाव लड़ रहे हैं।

अन्य सीटों पर भी यही स्थिति

- **सक्ती**- विधानसभा सीट सक्ती से भाजपा ने डा. खिलावन साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत लड़ रहे हैं। यहां एक निर्दलीय प्रत्याशी खिलावन साहू भी चुनावी मैदान में हैं।
- **भटगांव सीट**- भटगांव में कांग्रेस ने पारसनाथ राजवाड़े को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां निर्दलीय प्रत्याशी भी पारसनाथ राजवाड़े लड़ रहे हैं।
- **कोरबा**- कोरबा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी लखनलाल देवांगन के सामने हमनाम प्रत्याशी लखनलाल देवांगन चुनावी मैदान में हैं।
- **पाटन**- पाटन विधानसभा हाईप्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा से सांसद विजय बघेल लड़ रहे हैं। यह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अमित जोगी चुनावी मैदान में हैं। अमित कुमार हिरवानी भी आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं।
- **प्रतापपुर**- सरगुजा की प्रतापपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने शकुंतला सिंह पोर्ते चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शकुंतला भी चुनाव लड़ रही हैं।
- **रामानुजगंज**- विधानसभा सीट रामानुजगंज से कांग्रेस प्रत्याशी डा. अजय कुमार तिर्की चुनाव लड़ रहे हैं। यहां एक निर्दलीय प्र त्याशी अजय तिर्की भी चुनाव लड़ रहे हैं।
- **दुर्ग शहर**- दुर्ग शहर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण वोरा के नाम से एक निर्दलीय प्रत्याशी अरुण जोशी चुनाव लड़ रहे हैं।
- **रायपुर-दक्षिण**- रायपुर-दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कांग्रेस से महंत रामसुंदर दास चुनाव लड़ रहे हैं। यहां यहां दो ठाकुर जोहर छत्तीसगढ़ से मनीष कुमार ठाकुर और समाजवादी पार्टी से मनीष श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं।
- **महासमुंद**- महासमुंद सीट पर भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर राहू सिन्हा के सामने अंबिकापुर- सिंहदेव के सामने भाजपा से उनके ही करीबी राजेश

तीन बार से विधायक सिंहदेव के सामने भाजपा ने उनके ही करीबी और पुराने कांग्रेसी राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। अंबिकापुर में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों की संख्या स्थानीय लोगों से अधिक है। अधिकतर व्यापार-कारोबार यही लोग संभाल रहे हैं। आदिवासी मतदाता यहां निर्णायक की भूमिका में हैं। जिस कोयला खदान को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सियासत चल रही है, वह इस क्षेत्र के उदयपुर में है। राजपरिवार के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय है। शहर के रवि देवांगन कहते हैं, पिछले चुनाव में जिस उम्मीद से बाबा को जीत दिलाई गई थी, उसके पूरी नहीं होने से निराशा है। यूपी के सोनभद्र के मूल निवासी व्यापारी पप्पू जायसवाल ने कहा, भाजपा प्रत्याशी शहर के लिहाज से तो ठीक हैं, लेकिन इस सीट पर ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का रुख हार-जीत तय करता है।

सीतापुर- जवान टोप्पो ने बढ़ाई चार बार के विधायक और मंत्री भगत की मुसीबत

केंद्रीय सशस्त्र बल से वीआरएस लेकर सियासत में आए 32 साल के रामकुमार टोप्पो ने लगातार चार बार के विधायक और मंत्री अमरजीत भगत की जमीन हिला दी है। वीरता पुरस्कार से सम्मानित टोप्पो की युवाओं में जबर्दस्त लोकप्रियता से भगत सशंकित हैं। मसीही समाज भी भगत से बिफरा हुआ है। वजह यह कि संघ और भाजपा के धर्मांतरण विरोधी अभियान के खिलाफ भगत मसीही समाज के पक्ष में खुलकर नहीं आए। मसीही समाज ने स्वतंत्र उम्मीदवार भी उतार दिया है। इलाके से ताल्लुक रखने वाले गोविंद साहू के अनुसार, लगातार चार कार्यकाल के बाद भी अमरजीत भगत ने क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। टोप्पो युवा हैं और आधारभूत सुविधाओं के लिए तरसते मतदाताओं में उन्होंने उम्मीद जगाई है।

भरतपुर सोनहत- भाजपा की उम्मीद बड़ी रेणुका पर बाहरी का ठप्पा, गुटबाजी में फंसीं

अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित भरतपुर सोनहत से मैदान में उतरीं केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह की राह आसान नहीं है। पार्टी के स्थानीय दावेदार चुनाव में खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाए फिर रही है। रेणुका सोनहत इलाके को अपना मायका बताने में मेहनत कर रही हैं। 2008 और 2013 में भाजपा इस सीट पर काबिज रही। पिछले चुनाव में कांग्रेस के गुलाब कमरो भाजपा से यह सीट छीनने में कामयाब रहे। इस बार भी पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) का लगातार बढ़ता जनाधार भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी है। 2008 में गोंगपा प्रत्याशी ने यहां से लगभग नौ हजार, 2013 में 18 हजार और 2018 में 26 हजार से अधिक वोट पाए। सोनहत कस्बे में एक दुकान पर मिले मन्नूलाल कंवर बताते हैं, भाजपा ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। पिछली बार जीते कांग्रेस के गुलाब कमरो ने भी खास काम नहीं किया। सोनहत के कई ग्रामीण इलाकों में पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है सड़कें भी बदहाल हैं।

पत्थलगांव- रामपुकार के अनुभव को सांसद गोमती की चुनौती

पत्थलगांव सीट पर कांग्रेस से आठ बार के विधायक रामपुकार सिंह के सामने भाजपा ने रायगढ़ सांसद गोमती साय को उतारकर मुकाबला कड़ा कर दिया है। यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। संपर्क मार्गों की तो छोड़ें, मुख्य दूसरी तरफ, गोमती के लिए भी स्थानीय संगठन से सामंजस्य बैठाने की चुनौती है।

जशपुर- जूदेव परिवार की साख दांव पर

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव के 2013 में निधन के बाद भी जशपुर और आसपास के इलाकों में जूदेव परिवार का दबदबा कायम है। जूदेव परिवार की बहू संयोगिता सिंह बिलासपुर संभाग की चंद्रपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। संयोगिता दिलीप सिंह जूदेव के छोटे बेटे स्वर्गीय युद्धवीर सिंह की पत्नी हैं। दिलीप जूदेव के मंझले बेटे प्रबल प्रताप सिंह को भाजपा ने कोटा सीट से अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी के खिलाफ उतारा है।

मैनपाट- छत्तीसगढ़ के तिब्बत में विकास की दरकार

अंबिकापुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित मैनपाट की वादियों को छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। बताते हैं कि वर्ष 1962 के दौरान तिब्बत में विद्रोह के बाद वहां के शरणार्थियों को यहां भी बसाया गया। तिब्बतियों का जीवन एवं बोध मंदिर यहां आकर्षण का केंद्र है। सर्दियों में यहां का तापमान शून्य से नीचे भी चला जाता है। यह मांड और रिहंद नदी का उद्गम स्थल भी है। यह पामेरियन कुत्तों और कालीन के लिए भी जाना जाता है। हालांकि, इतनी विशेषताओं के बाद भी तमाम सरकारें आईं और गईं पर यहां पर्यटन की संभावनाओं को अवसर में बदलने की इच्छाशक्ति किसी ने नहीं दिखाई।

रायपुर ग्रामीण में भितरघात, कांग्रेस-भाजपा दोनों में अंदरूनी कलह

राजधानी के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों को भितरघात का डर सता रहा है। हालात ऐसे हैं कि बिरगांव, सेजबहार, डूंडा, बोरियकला, बोरियाखुर्द, दतरेंगा, कांदूल, माना बस्ती समेत आसपास के गांवों में कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध उनकी ही पार्टी के पार्षद, नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी अंदर ही अंदर कर रहे हैं, जबकि भाजपा के पूर्व विधायक रहे नंदकुमार साहू, दावेदार रविंद्र सिंह, ओमप्रकाश देवांगन भाजपा के समर्थन में मोतीलाल साहू के साथ प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं टिकट न मिलने की कमी उन्हें भी खल रही है। हालांकि खुलकर कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा है। इससे साफ है कि कांग्रेस-भाजपा दोनों में अंदरूनी कलह और भितरघात की आग तेजी से फैल रही है। इसका नुकसान दोनों दलों के प्रत्याशियों को उठाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

साहू समाज की बहुलता वाली इस सीट पर मोतीलाल साहू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करने वाले भी चुनाव प्रचार से गायब दिखाई दे रहे हैं। साहू समाज के कई निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्षद, पदाधिकारी समेत अन्य कसडोल से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप साहू के चुनाव प्रचार करने शहर छोड़कर कसडोल में डटे हुए हैं। बिरगांव में छत्तीसगढ़ियावाद भी सामने आ गया है। यहां कुछ विभिन्न स्थानीय संगठन कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं।

रायपुर की चार सीटों में से एक ग्रामीण विधानसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने यहां से विजय हासिल की थी। इस बार उनकी जगह पर कांग्रेस ने उनके बेटे पंकज शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने साहू समाज का कार्ड खेलते हुए मोतीलाल साहू को मैदान में उतारा है। लिहाजा इस बार भाजपा पूरे दम-खम के साथ चुनावी मैदान में चुनौती दे रही है। हालांकि दोनों प्रत्याशी के धुंआधार चुनाव प्रचार को देखते हुए यह कह पाना जरा मुश्किल है कि बाजी कौन मारेगा? ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस या भाजपा किसका सिक्का चलेगा, यह 17 नवंबर को ही साफ होगा। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में रायपुर ग्रामीण सीट पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा गया था, वहीं भाजपा की ओर से नंदकुमार साहू चुनाव मैदान में थे। यह चुनाव कांटे की टक्कर का हुआ था, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई थी। भाजपा के उम्मीदवार को जहां 68 हजार से कुछ अधिक वोट ही मिल सके थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने 78 हजार से अधिक वोट लाकर विजयश्री हासिल की। इस साल हो रहे चुनाव में रायपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से दोनों ही पार्टियों से नए प्रत्याशी आमने-सामने हैं। अब देखना रोचक होगा कि किस दल के पक्ष में मतदाता अपना वोट देते हैं। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के सेजबहार, डूंडा, कांदूल, दतरेंगा, मुजगहन,माना बस्ती, भनपुरी आदि झुग्गी क्षेत्र का जाएजा लेकर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की। अधिकांश मतदाताओं ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा लेकिन इतना जरूर कहा कि जो विकास का काम करेगा, उसे ही विधायक चुनेंगे। क्षेत्र के कई घर ऐसे हैं, जहां एक परिवार के कुछ कांग्रेस तो कुछ भाजपा से प्रभावित दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर मतदाताओं के बीच फिलहाल खामोशी है। यह खामोशी 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान के दिन ही टूटेगी।

सरगुजा को फिर मुख्यमंत्री मिलने की आस

अबकी बार भाजपा ने रेणुका सिंह पर खेला दांव

सरगुजा संभाग के मतदाताओं का मन-मिजाज बदला नजर आ रहा है। मूल सुविधाओं से जूझते क्षेत्र के मतदाताओं ने पिछले चुनाव में बड़ी उम्मीद से कांग्रेस को सभी 14 सीटें न्योछावर कर दी थीं। उन्हें उम्मीद थी कि राजपरिवार के टीएस बाबा (उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव) मुख्यमंत्री बनेंगे पर ऐसा हुआ नहीं। मतदाताओं को इस बार भरतपुर-सोनहत से भाजपा प्रत्याशी जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह में नई उम्मीद नजर आई है। उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि भाजपा आई तो प्रदेश को पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री सरगुजा से ही मिलेगी। केंद्र में मंत्री होने के नाते मतदाता भी दावों में दम देख रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में उम्मीद के अनुरुप काम न कर पाने से कांग्रेस की राह आसान नहीं है। सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए पार्टी ने चार विधायकों के टिकट काटे हैं। इससे हुई बगावत थम नहीं रही। भाजपा इसे अवसर के रूप में देख रही है। इस बार 12 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें रेणुका सिंह, रायगढ़ से सांसद गोमती साय और पूर्व केंद्रीय मंत्री व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे विष्णुदेव साय हैं। अवैध धर्मांतरण पर मुखर भाजपा ने लुंड्रा सीट से जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मसीही समाज के प्रबोध मिंज को मैदान में उतारा है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रियंका गांधी के छोटे कद वाले बयान पर सिंधिया का पलटवार

भोपाल। सिंधिया ने प्रियंका गांधी को पलटवार में पार्ट-टाइम नेत्री बताया। उन्होंन कहा कि क़ाबिलियत को क़द से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले, कृपया स्वयं आईने में झांक लें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों और वादाखिलाफ़ियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है, और पुन: आपका सूपड़ा साफ़ मध्यप्रदेश से जनता करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वालीं प्रियंका गांधी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए भी एक पर्चे पर लिखी लाइनों की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है, इसका अंदाज़ा भी लग गया। ग्वालियर-चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निम्न स्तर के भाषण का उत्तर ज़रूर 17 नवंबर को अपना मतदान करके दें, और कांग्रेस पार्टी को सबक़ सिखाएं।

जमीन घोटाला: दिल्ली सरकार ने सीबीआई को भेजा मामला

नईदिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में कथित 850 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हरी झंडी के बाद मामला सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजा गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजे जाने के एक दिन बाद ही यह घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें नौकरशाह को तत्काल हटाने और निलंबित करने की मांग की गई है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर अपने बेटे करण चौहान से जुड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन की कीमत 22 गुना बढ़ाने का आरोप है।

दिल्ली प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार पर बरसे उपराज्यपाल

नईदिल्ली। दिवाली के बाद गुरुवार को चौथे दिन भी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहने पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए अन्य राज्यों को दोष देना कोई समाधान नहीं है और असली समाधान दिल्ली में ही है। एलजी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली को केवल दिखावे की नहीं, बल्कि कार्रवाई की जरूरत है और कहा कि राजनीति इंतजार कर सकती है। उपराज्यपाल ने कहा, हम दूसरे राज्यों से आने वाले पराली के धुएं को रोकने के लिए उनसे गुहार लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। राज्यों, विशेषकर पंजाब के उदासीन रहने के बावजूद, हम दया के लिए याचिकाकर्ता हैं। एक्यूआई अभी भी 400 के आसपास है, जिससे राजधानी हांफ रही है। पटाखे निश्चित रूप से खतरे को बढ़ाते हैं। इस गैस चैंबर से सबसे ज्यादा प्रभावित वे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पर सफर करते हैं।

पूर्व सांसद विजयशांति ने भाजपा से दिया इस्तीफा

हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले सूबे में सत्ता पाने के लिए जोर लगा रही भारतीय जनता पार्टी को बेहद तगड़ा झटका लगा है। जी हां, पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री विजयशांति ने बीते बुधवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पार्टी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि पूर्व सांसद विजयशांति ने अपना इस्तीफा औपचारिक रूप से भाजपा प्रदेश प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को भेज दिया है। खबरों के अनुसार उन्होंने यह कदम पूर्व सांसद विवेक वेंकटस्वामी और पूर्व विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी सहित अन्य नेताओं के भाजपा छोड़े जाने के बाद लिया है। बताया जा रहा है कि विजयशांति ने भाजपा की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया है, जिसके कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया।

17 नवंबर को 3 आर आधारित होंगे इंदौर के मतदान केंद्र

इंदौर। इंदौर नगर निगम ने 17 नवंबर को मतदान के लिए शहर में 3 आर, स्मार्ट, पिंक, विशिष्ट थीम पर आदर्श मतदान केन्द्र बनाया है। इन आदर्श मतदान केन्द्र में पर्यावरण से संबंधित थीम को लेकर सजावट की है। नगर आयुक्त ने कहा है कि वोट डालने आए मतदाताओं को मतदान के तहत जागरूक करना है और उन्हें केन्द्र पर जंगल का भी अनुभव कराया जाएगा। 3 आर थीम पर बनाए गये, आदर्श मतदान केन्द्र पर शहर के विभिन्न 3 आर सेंटर से एकत्रित अनुपयोगी सामान से मतदान केन्द्र की साज-सज्जा की गई है। इसका मुख्य उददेश्य है कि शहर के नागरिक यह देखे कि किस प्रकार से घर से निकलने वाले अनुपयोगी सामान से भी आकर्षक साज-सज्जा की जा सकती है। आयुक्त ने कहा कि इंदौर में आगामी विधानसभा निर्वाचन को ऐतिहासिक स्वरूप देने के उद्देश्य से शहर में बनाये जा रहे आदर्श मतदान केन्द्र को अलग-अलग थीम पर बनाया गया है।

भाजपा ने गरीबों का किया उत्थान : जेपी नड्डा

राजस्थान में बोले भाजपा अध्यक्ष- अंधेरा लाती है कांग्रेस

जयपुर। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है। दौसा जिला की महुवा विधानसभा में आयोजित जनसभा को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंन कहा कि हमारा मकसद केवल किसी को विधायक बनाना नहीं है। बल्कि हमारा मकसद है इनके माध्यम से दौसा का विकास हो और यहां के विधायक आपकी आवाज बनें। उन्होंने कहा कि आपको तय करना पड़ेगा कि कौन रक्षक है और कौन भक्षक। कौन आपकी रक्षा करता है और कौन आपके हकों पर डाका डालता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है - भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, आपके हकों पर डाका, वंशवाद, परिवारवाद और सेवा के नाम पर मेवा खाना। जबकि भाजपा का मतलब है- विकास, तरक्की, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार, महिलाओं-किसानों-युवाओं को हक दिलाना और राजस्थान को एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाना। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस का पता लापता है, इनके राज में -बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, विकास लापता। इन्हें केवल एक ही चीज का पता है और वो है भ्रष्टाचार।

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अंधेरा लाती है। वहीं भाजपा सौभाग्य योजना और उजाला योजना के माध्यम से आपको अंधकार से दूर करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपको गरीबी की तरफ धकेलती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी देश की 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन देते हैं और साढ़े 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर विकास की ओर लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि आज कल बहुत से कांग्रेसी नेताओं को प्रभु राम बहुत याद आने लगे हैं। ये वही कांग्रेसी हैं, जिन्होंने कोर्ट में लिख कर दिया था कि राम काल्पनिक हैं, इनका कोई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार नहीं है। आजकल ये राम-राम जप रहे हैं।

सिकराय विधानसभा में आयोजित जनसभा में नड्डा ने कहा कि मैं यहां के युवाओं, महिलाओं और यहां की जनता में जो उत्साह देख रहा हूं, उससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की जीत तय है। अगले 5 सालों में सिकराय की तकदीर और तस्वीर बदले और विकास के पथ पर चले, यही हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान की सरकार महिला उत्पीड़न के रूप में जानी जाती है,

महिलाओं के साथ अन्याय के रूप में जानी जाती है। किसानों के साथ धोखा किया, छल किया और किसानों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए जानी जाती है। जो राजस्थान शांति प्रिय था, आज वहां सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, इसलिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आज राजस्थान रेप और बलात्कार में नंबर एक पर खड़ा है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की विधायक का पति भी रेप और मर्डर केस में फंसा है और खुलेआम घूम रहा है।

राजस्थान में भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ गुरुवार को राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) जारी किया। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य पार्टी प्रमुख सीपी जोशी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। विशेष रूप से, मेघवाल ने दावा किया कि भाजपा का संकल्प पत्र पार्टी के आउटरीच कार्यक्रमों जैसे आकांक्षा पेटी, ई-मेल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक लोगों के सुझावों पर आधारित है। मेघवाल पार्टी की घोषणापत्र समिति के संयोजक हैं। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को पिछले 9 वर्षों में 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिसमें से 11 ऑपरेशनल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भारत सरकार ने राज्स्थान के लिए विकास कार्य किया है, लेकिन हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं।

भले ही भाजपा जीत जाए पर..., फर्जी वीडियो को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना

जयपुर। लोकसभा चुनाव से पहले पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां प्रचार खत्म हो चुका है वहीं, राजस्थान और तेलंगाना में जबरदस्त तरीके से जारी है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार में दम दिखाने को तैयार हैं। इसकी शुरूआत उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कर दिया है। उन्होंने कहा कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में मतदान पूर्व 'चाहे भाजपा जीत जाए किन्तु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए' जैसा विशुद्ध गलत व फर्जी वीडियो का कांग्रेस द्वारा प्रचारित करना दुर्भाग्यपूर्ण व उनकी हताशा का प्रतीक है। यह षडयंत्र बीएसपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए है। लोग सावधान रहें। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस का इन राज्यों में अति-मिथ्या प्रचार जारी है, जबकि बीएसपी द्वारा चुनावी सभाओं में लोगों से वोट देने तथा विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि हथकण्डों से सावधान रहने की अपील की गयी, जो पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की बौखलाहट से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि अब जबकि मतदान नजदीक है। विरोधी पार्टियों में भी खासकर कांग्रेस द्वारा, भाजपा से मजबूती से लड़ने के बजाय, बीएसपी विरोधी अपनी पुरानी नापाक हरकतों व साजिशों को जारी रखना घोर अनुचित व दुर्भाग्यपूर्ण, जिससे लोग सावधान रहें तथा चुनाव आयोग भी इसका समुचित संज्ञान ले। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मायावती यह कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि कांग्रेस द्वारा खड़े किए जाने वाले दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए बीएसपी अपनी पूरी ताकत लगा देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को हराने के लिए चाहे बीजेपी उम्मीदवार को ही वोट क्यों ना देना पड़ जाए, वो भी देंगे। इस वीडियो को बसपा प्रमुख ने फेक बताया है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है।

राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस में कलह की खबरों को किया खारिज

हम न केवल एक साथ दिख रहे हैं बल्कि एकजुट भी हैं

जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के बीच राजस्थान कांग्रेस में चल रही कलह और गुटबाजी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी एकजुट है और भाजपा को हराने के पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। राहुल गांधी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ दिखे और उन्होंने कहा कि हम न केवल एक साथ दिख रहे हैं बल्कि हम एकजुट भी हैं।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को जयपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हम न केवल एक साथ दिख रहे हैं बल्कि एकजुट भी हैं। हम एक साथ रहेंगे और कांग्रेस यहां चुनाव जीत रही है।

राहुल गांधी का पार्टी के लिए दिया एकजुटता का संदेश उस वक्त में आया है, जब मीडिया हलकों में खबरें चल रही हैं कि राजस्थान कांग्रेस सदस्यों के नेताओं में अंरूनी कलह और गुटबाजी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का बी दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी नये सिरे से विवाद शुरू हो गया है।

ऐसे माहौल में राहुल गांधी का राजस्थान दौरा पार्टी के भीतर गुटबाजी की खबरों को खारिज करने के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने मतदान होना है और कांग्रेस दावा कर रही है कि वो फिर से सत्ता में वापसी कर रही है।

इससे पहले बुधवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान कांग्रेस के भीतर फूट की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सभी नेता एक साथ मिलकर पार्टी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे।

उन्होंने कहा, ऐसी कहानी फैलाई जा रही है कि

राजस्थान में कांग्रेस के भीतर कोई एकता नहीं है। हालांकि, मैं दावा कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी पहले की तरह एकजुट है। हमारे सभी नेता एक साथ खड़े हैं और भाजपा की हार सुनिश्चित करने और वापसी सुनिश्चित करने के सामान्य उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं। मालूम हो कि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

सचिन पायलट ने कहा है कि पार्टी ने जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं और कुल मिलाकर टिकट वितरण बहुत निष्पक्ष रहा है। अपने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच खींचतान के बारे में बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा, हमें आगे बढ़ना होगा, जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए, जो भी कहा गया, उसे हमें भूलना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे छोड़ो! किसने क्या कहा...मैंने जो कहा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हो सकता हूं। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक चर्चाओं में गरिमा और प्रवचन बनाए रखना चाहिए। जिसने भी वे सभी शब्द कहे हैं जिनका आपने उल्लेख किया है, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि मैं इस तरह से नहीं बना हूं और हमें अब आगे बढ़ना होगा, जो कुछ भी कहा गया था उसे भूल जाना चाहिए, हमें भूलने और आगे बढ़ने की जरूरत है।

खेल
प्रमुख समाचार

शमी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक : विलियमसन

नईदिल्ली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद मोहम्मद शमी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक और भारतीय टीम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम करार दिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई। न्यूजीलैंड की टीम 398 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 48.5 ओवर में 327 रन पर आउट हो गई थी। शमी ने 57 रन देकर सात विकेट लिए। यह मौजूदा वर्ल्ड कप में तीसरा अवसर है जबकि उन्होंने एक मैच में पांच या इससे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया। शमी अभी तक मौजूदा वर्ल्ड कप में 23 विकेट ले चुके हैं।

विलियमसन ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''उनका (शमी) प्रदर्शन अविश्वसनीय है। वह शायद आधे मैच ही खेल पाए हैं लेकिन टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हैं।'' उन्होंने कहा,''इसमें कोई संदेह नहीं कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। वह जिस तरह से गेंद को मूव कराते हैं और स्टंप को खेल का हिस्सा बनते हैं वह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने इतने कम मैच में जितने विकेट लिए हैं वह शानदार है।''

विलियमसन ने कहा,''भारत की यह टीम निसंदेह खेल के हर विभाग में शानदार प्रदर्शन कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसका पूरा ध्यान अब अगले मैच पर होगा।'' न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारतीय टीम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम करार देते हुए कहा कि विरोधी टीम के लिए उनका सामना करना मुश्किल है क्योंकि उसके सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''वह इस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है और उसके सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए उनका सामना करना मुश्किल है। वह वास्तव में जरा सी चूक नहीं दिखा रहे हैं।''

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 307 अंक चढ़ा निफ्टी 19,750 के पार

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गुरुवार को हरे निशान पर बंद हुए। दिन के कारोबार के अंतिम दौर में बैंकिंग शेयरों में आई बिकवाली से हालांकि तेजी में कमी आई। दिन के उच्चतम स्तर पर सेसेंक्स 682 अंकों से भी ज्यादा मजबूत था। आज ग्लोबल मार्केट में कमजोर रुझान देखे गए। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 307 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 87 अंक की बढ़त दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 306.55 अंक यानी 0.47 फीसदी की बढ़त के साथ 65,982.48 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,358.37 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,507.02 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 87.10 अंक यानी 0.44 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,762.55 अंक पर बंद हुआ।

बंद होने वाली है यूपीआई आईडी!

नईदिल्ली। ऑनलाइनमनी ट्रांसजेक्शन के लिए हम सभी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। भारत में यूपीआई को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स काफी है क्योंकि यह बहुत आसान प्रक्रिया है। अब यूपीआई यूजर्स के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है जो आपकी यूपीआई आईडी को निष्क्रिय कर देंगे। सभी बैंक और गूगल पे और फोन पे जैसे थर्ड-पार्टी ऐप उन यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने जा रहे हैं जिनमें एक साल से अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं किया गया है। इस साल के अंत तक ऐसे सभी यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा जिनसे कोई ट्रांसजेक्शन नहीं हुआ है। एनपीसीआई ने बैंकों और थर्ड-पार्टी ऐप्स को इन यूपीआई आईडी की पहचान करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

जापान का निर्यात अक्टूबर में 1.6% बढ़ा, आयात 12.5% घटा

नईदिल्ली। जापान के निर्यात में अक्टूबर में सालाना आधार पर 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वाहन और जहाज का निर्यात बढ़ने से यह वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शेष एशियाई देशों में निर्यात में गिरावट आई है, जबकि अमेरिका तथा यूरोप में निर्यात में वृद्धि हुई है। वहीं जापान का आयात अक्टूबर में 12.5 प्रतिशत गिरावट के साथ 9800 अरब येन (64 अरब डॉलर) हो गया। इसकी मुख्य वजह तेल, गैस और कोयले की कम लागत रही। कंप्यूटर के हिस्सों तथा अनाज का आयात भी कम रहा, जबकि स्टील के आयात में वृद्धि हुई। अक्टूबर में 9150 अरब येन (60.5 अरब डॉलर) के निर्यात के साथ व्यापार घाटा सालाना आधार पर 70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 662.5 अरब येन (4.4 अरब डॉलर) हो गया। मूडीज एनालिटिक्स के अर्थशास्त्री स्टीफन एंग्रीक ने कहा, ''निर्यात ने इस साल की पहली छमाही में मजबूत वृद्धि को आगे बढ़ाने में मदद की।

सरकार ने क्रूड ऑयल, डीजल पर विंडफॉल टैक्स घटाया

नईदिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में नरमी के बाद सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल तथा डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में गुरुवार को कटौती की। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या एसएईडी के रूप में लगाया जाने वाला कर 9,800 रुपये प्रति टन से घटाकर 6,300 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल के निर्यात पर एसएईडी को दो रुपये प्रति लीटर से घटाकर एक रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। विमान ईंधन या एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रहेगा। नई कर दरें गुरुवार से लागू हो गईं। इससे पहले एक नवंबर को दरों में संशोधन करते हुए सरकार ने कच्चे तेल पर कर 9,050 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति टन कर दिया था।

कोरोना के असर से उबरती अर्थव्यवस्था, बढ़ रहा है उपभोक्ताओं का भरोसा

पीएस वोहरा

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खुशी की बात है कि जिस तरह से इन दिनों हर तरफ त्योहारों की छटा छाई हुई है, भारतीय उपभोक्ताओं का विश्वास भी अब अर्थव्यवस्था के प्रति बढ़ रहा है। उपभोक्ताओं की भावनाओं से संबंधित रिजर्व बैंक की एक नई रिपोर्ट इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें बताया गया है कि अब भारतीय समाज से कोरोना का आर्थिक दुष्प्रभाव पूर्णत: खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। केंद्रीय बैंक की इस रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े सितंबर में हुए एक सर्वे पर आधारित हैं। इस रिपोर्ट के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि सितंबर में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स (सीसीआई) 92.2 पर दर्ज हुआ, लगभग इसी स्तर से कुछ ऊपर यह इंडेक्स वर्ष 2019 में था। यानी देश की आर्थिक नीतियों की चाल सही दिशा की ओर अग्रसर है।

रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला यह सर्वे मुख्यत: पांच आर्थिक तथ्यों पर भारतीयों के विचार व भावनाओं को जानने की कोशिश करता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति, रोजगार का वर्तमान स्तर, महंगाई व उसका प्रभाव, व्यक्तिगत आर्थिक आय में बढ़ोतरी या गिरावट तथा विभिन्न प्रकार के खर्चों का विश्लेषण सम्मिलित होता है। इस सर्वे का एक अन्य पक्ष यह भी है कि यह वर्तमान स्थिति के विश्लेषण के साथ-साथ भविष्य के प्रति भारतीयों के आर्थिक विकास के नजरिये को भी जानने की कोशिश करता है। कोरोना की आर्थिक मार पड़ने के बाद वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 तक सीसीआई गिरकर तकरीबन 40 अंक के स्तर पर चला गया था। मगर ये आंकड़े बताते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क तीन वर्षों में ही आर्थिक गिरावट के दौर से

बाहर निकल आया है।

इन सबके बावजूद भारतीय समाज का आम व्यक्ति रोजगार में बढ़ोतरी के संबंध में बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं है। रिजर्व बैंक के इसी सर्वे में लगभग दो तिहाई से अधिक लोगों ने माना है कि रोजगार की उपलब्धता के संबंध में अब भी स्थिति लगभग एक वर्ष पहले जैसी ही है और तकरीबन 10 प्रतिशत से अधिक लोगों ने रोजगार की बढ़ोतरी के संबंध में अपनी राय ही नहीं दी है। आगामी वर्ष के लिए रोजगारों में बढ़ोतरी के संबंध में तकरीबन 30 प्रतिशत लोगों ने अपनी राय रखने से मना कर दिया। 25 प्रतिशत से अधिक लोगों ने माना कि एक वर्ष बाद रोजगारों के स्तर में भारतीय अर्थव्यवस्था में कमी देखने को मिलेगी। वहीं 18 प्रतिशत लोगों ने माना कि एक वर्ष बाद की स्थिति ऐसी ही रहेगी। आम भारतीय रोजगारों की बढ़ोतरी के संबंध में ज्यादा आशान्वित नहीं है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो सरकारी क्षेत्र में रोजगारों की उपलब्धता बहुत कम है, दूसरे निजी क्षेत्र में हमेशा अस्थिरता ही ज्यादा देखने को मिलती है। पिछले तीन दशकों में भारत में बेरोजगारी की दर कभी भी पांच प्रतिशत से नीचे नहीं रही, परंतु इस अवधि में मुल्क की आबादी 50 करोड़ के आसपास बढ़ी। यानी बेरोजगारों की संख्या भारत में प्रतिवर्ष बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसी कारण भारत 'रोजगार विहीन आर्थिक विकास' वाले मुल्क के रूप में जाना जाता है। भारत को इस समस्या से निजात मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर ही दिला सकता है। लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का देश के निर्यात में दो प्रतिशत से भी कम हिस्सा है, जबकि हमसे कम आबादी वाले वियतनाम का मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का निर्यात में अंशदान तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है। एशिया में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में भारत का मुकाबला अब चीन से ही नहीं, अपितु कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं से भी है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलयेशिया, ताइवान, फिलीपींस, कोरिया और बांग्लादेश भी बड़ी तेजी से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि इन सभी देशों के उत्पादों की लागत भारतीय उत्पादों से तकरीबन 20 से 30 प्रतिशत तक कम है।

इसके अलावा, एक लंबे अरसे से सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, परंतु इसके द्वारा रोजगारों का सृजन समाज के सभी तबकों तक नहीं पहुंच रहा है। शायद इसीलिए बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है।

भाजपा की जीत सुनिश्चित. प्रदेश के कर्मियों की समस्याएँ हल होने का रास्ता खुलने जा रहा है: चौधरी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि दिसंबर में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही 100 दिनों के भीतर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने एक कमेटी का गठन करने के लिए संकल्पित है। इस समिति में अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी सदस्य होंगे।

श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा को इन विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित हो चुकी है और इसी के साथ प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याएँ हल होने का रास्ता खुलने जा रहा है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कदम उठाएगी। भाजपा सरकार पंचायत सचिवों को नियमित कर उनका बकाया एरियर पीपीएफ में जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में दिसंबर में बनने जा रही भाजपा की सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे डी.ए. के समान डी.ए. देगी। भाजपा सरकार मितानिन (आशा) कर्मचारियों को एनएचएम के अंतर्गत स्थायी रूप से लिए जाने के लिए केंद्र सरकार के साथ चर्चा कर पहल करेगी। श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार मितानिन कर्मचारियों के मासिक मानदेय और शिक्षा विभाग में कार्यरत सफाई कर्मी व मध्याह्न भोजन रसोइयों के वेतन में 50 फीसदी की वृद्धि करेगी। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस क्वार्टर्स के निर्माण के लिए पुलिस कल्याण कोष को सशक्त करेंगे जबकि वादे के बावजूद कांग्रेस की भूपेश सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया और इसे लेकर पुलिस कर्मियों को आंदोलन तक करना पड़ा जिसमें उनके परिजनों से दुर्व्यवहार तक किया गया। कांग्रेस सरकार ने अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को वादा करके भी नियमित नहीं किया।

बृजमोहन को मिला सर्व समाज का आशीर्वाद रायपुर दक्षिण में फिर खिलेगा कमल

■ मतदान के पूर्व विभिन्न सामाजिक बैठकों में शामिल हुए बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। सभी समाजों के समक्ष अपनी बात रखते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पिछले 35 सालों से मैं रायपुर शहर की सेवा में लगा हुआ हूं। शहर में निवासरत प्रत्येक समाज मेरा अपना है। समाज के वरिष्ठों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही मैं क्षेत्र में विकास करता रहा हूं। रायपुर दक्षिण विधानसभा में जितने भी सामाजिक सामुदायिक भवन बने हैं उसने किसी अन्य विधानसभा में शायद ही बना हो।

रायपुर दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मतदान के पूर्व दिवस क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क किया और लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बृजमोहन अग्रवाल ने पुरानी बस्ती, मठपारा मठ पुरैना, चंगोरा भाटा, क्षेत्र में विभिन्न समाजों द्वारा आयोजित बैठकों में शामिल हुए और उनके समक्ष अपनी बात रखी। विशेष रूप से ब्राह्मण समाज,साहू समाज, देवांगन समाज, धीवर समाज के प्रमुख लोगों द्वारा आयोजित बैठकों में श्री अग्रवाल को लोगों ने जीत का आशीर्वाद दिया।

उन्होंने बैठकों में उपस्थित सामाजिक लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि बीते 5 वर्षों में रायपुर शहर सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ का बुरा हाल प्रदेश की इस कांग्रेस सरकार ने कर रखा है। भ्रष्टाचार चरम पर है प्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ का कर्ज़ इस कांग्रेस सरकार ने लाद दिया है। विकास के कार्य शून्य है ऐसे में जनता के पास यह मौका है कि वह विकास की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करें जन भावनाओं की अनुरूप कार्य करने वाली भाजपा की सरकार बनाएं।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बगैर भेदभाव के क्षेत्र के सभी वार्डों, मोहल्लों और बस्तियों का विकास हमने किया है। शहर के प्रत्येक नागरिक के लिए उनके विधायक बृजमोहन का निवास 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म व दल का हो मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। सभी की समस्याओं व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना सहयोग दिया है। ऐसे में मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि रायपुर शहर की जनता का आशीर्वाद कमल फूल में मतदान के रूप में मुझे प्राप्त होगा।

भाजपा सरकार बनते ही विकास के नए रास्ते खुलेंगे और संत्रास से मुक्ति मिलेगी : डॉ. पांडेय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. सरोज पांडेय ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की तरह ही मतदान के द्वितीय चरण में भी भाजपा के पक्ष में मतदान करने का निश्चय प्रदेश के मतदाता कर चुके हैं और अब कांग्रेस की विदाई तय हो चुकी है। डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि कांग्रेस सरकार के जाते ही और दिसंबर में भाजपा सरकार बनते ही प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, मान-सम्मान और विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे और अपराध, उत्पीड़न व अपमान के संत्रास से उन्हें मुक्ति मिलेगी।

भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद डॉ. पांडेय ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के कुशासन में महिलाओं के आत्मसम्मान और अस्मिता को कदम-कदम पर लहूलुहान होते पूरे पाँच साल तक प्रदेश ने देखा है। महिला सुरक्षा के नाम पर कोरी ढपोरशंखी शेखी बघारती कांग्रेस की भूपेश सरकार को अपने झूठे दावों पर शर्म तक महसूस नहीं हो रही थी। महिलाएँ एक तो घरेलू हिंसा से जूझने के लिए मजबूर थीं, वहीं लगातार दुष्कर्म-सामूहिक दुष्कर्म की वारदातों ने दरिंदों के हौसले सत्तावादी राजनीतिक संरक्षण के चलते इस कदर बढ़ा दिए कि तीन साल की मासूम बालिकाओं से लेकर वृद्ध महिलाएँ अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए मोहताज हो गईं। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़े इन मामलों में अधिकांश में तो कांग्रेस नेता ही शामिल रहे। हर कदम पर खुद को असुरक्षित पा रहीं इन महिलाओं को अब भाजपा सरकार बनते ही मुक्ति मिलेगी। भाजपा सरकार किसी भी अपराधी को कतई नहीं बख्शेगी और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालेगी। भाजपा सरकार बनते ही महतारी वंदन योजना जहाँ महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त होने का अवसर प्रदान करेगी, वहीं हर जिले में महिला थानों की स्थापना महिलाओं को दरिंदगी और तमाम अपराधों से सुरक्षित रखेगी। डॉ. पांडेय ने अपील की कि प्रदेश की मातृ-शक्ति अपराध और असुरक्षा मुक्त परिवेश के लिए भाजपा के पक्ष में शत-प्रतिशत मतदान करने की अपील की है।

70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसी तांडव की आशंका: सांसद सोनी

■ चीफ इलेक्शन ऑफिसर से शराब, पैसा वितरण की शिकायत

रायपुर। सांसद सुनील सोनी ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से शिकायत करते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा अवैध रूप से सामग्री वितरण, पैसा वितरण, शराब वितरण के साथ ही गुंडागर्दी करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। राज्य में बलवा होने की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने भाजपा की ओर से राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा किया जा रहा है। इस कारण चुनाव में शांति भंग होने की आशंका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मारपीट, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में भय व्याप्त है। इसकी शिकायत विभिन्न थानों में की गई है। लेकिन अब भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस और प्रशासन तंत्र निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होने के बावजूद कांग्रेस सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहा है।

सांसद सुनील सोनी ने कहा कि मतदान पूर्व की आज रात्रि एवं कल मतदान के दिन तक हर जगह अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। आपराधिक तत्वों की सक्रियता बढ़ रही है। मतदाताओं को प्रलोभन देने हेतु शराब, साड़ी, कम्बल एवं दूसरी सामग्रियों का वितरण देर रात तक किया जा रहा है जो कि आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से हमारी अपेक्षा है कि छत्तीसगढ़ की सभी 70 सीटों में स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान हो सके।

भाजपा सरकार किसानों के कल्याण और उनके जीवन-स्तर में सुधार लाने पहले दिन से प्रतिबद्ध रहेगी : बघेल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक व सांसद विजय बघेल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करके भाजपा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है, जो प्रदेश के लाखों किसानों के कल्याण और उनके जीवन-स्तर में सुधार लाने के अपने संकल्पों पर पहले दिन से ही प्रतिबद्ध रहेगी। श्री बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही %कृषक उन्नति योजना% के तहत प्रदेश के किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा जाएगा। दो साल के बकाया बोनस का भुगतान भी 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटलजी के जन्मदिवस पर किया जाएगा। भाजपा सांसद श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार के कुशासन के चलते प्रदेश के 700 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। गौठानों में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला तो किया ही, गोबर में घोटाला करके कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया। इसी प्रकार भूपेश सरकार ने लाखों किसानों को %प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि% के लाभ से वंचित रखा। श्री बघेल ने कहा कि दिसम्बर में भाजपा सरकार बनते ही किसानों को उनकी बेची गई।

कांग्रेस ने प्रदेश में उद्योगों के विकास पर नहीं दिया ध्यान: अजय चंद्राकर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि दिसंबर में भाजपा सरकार के बनते ही प्रदेश में ठप पड़े औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और छत्तीसगढ़ की राजधानी को मध्य भारत का इनोवेशन हब के रूप में विकसित कर राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हम इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित कर वार्षिक वैश्विकस्तरीय सम्मेलन कर देशी व विदेशी कंपनियों से निवेश आमंत्रित करेंगे।

भाजपा मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री चंद्राकर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में उद्योगों के विकास पर ध्यान देने के बजाय

आर्थिक विकास का अभिन्न अंग, स ड क , बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। श्री चंद्राकर ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में युवाओं के लिए रोजगार आवास पैदा करते अत्याधुनिक आईटी पार्क स्थापित करेगी। हम छत्तीसगढ़ आईटी टैलेंट विकास योजना के माध्यम से विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और आकर्षक प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योगऊ्अकादमिक सहयोग की सुविधा प्रदान करेंगे। प्रदेश के हर जिले में छत्तीसगढ़िया उत्पाद उद्यमी केंद्र स्थापित कर एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और राज्य की राजधानी में शॉपइ्सी.जी. ब्रांड नामक उत्पाद स्टोर खोलकर हर जिले को एक निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। प्रदेश में फार्मास्युटिकल पार्क स्थापित करेंगे। प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करेंगे। भाजपा सरकार सालाना ग्लोबल छत्तीसगढ़ स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित कर प्रदेश के महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक बेहतर वैश्विक नेटवर्क स्थापित कर युवाओं के लिए निवेश और रोजगार के अवसर में वृद्धि सुनिश्चित करेगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

75 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी : दीपक बैज

रायपुर। दूसरे चरण के मतदान के पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम पहले चरण के समान ही दूसरे चरण में भी जनता का भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगा। 75 सीटों के साथ प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने अपने 5 सालों के कामों के आधार पर जनता से वोट मांगा। हम पूरे चुनाव को सकारात्मक तरीके से लड़े। हमारा प्रयास था कि हम अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे। हमारी सरकार ने पिछले पांच सालों में जो काम किया था हमारे वोट मांगने का वही बड़ा आधार था। हमारी सरकार ने किसान, मजदूर, युवाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को सशक्त बनाने के लिये ठोस योजनायें बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन किया। ऋण माफी, धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली। हमने 5 सालों में बेरोजगारी, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिससे प्रदेश की 40 लाख आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आ गयी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 2018 में जिन वादों के आधार पर कांग्रेस को जनादेश मिला था, हमारी सरकार ने 5 सालों में उन वादों को पूरा कर दिखाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरी।

भाजपा को वोट देना मतलब धोखेबाजों को संरक्षण देना: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र पर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरा पर भरोसा कर रही है जनता जानती है भाजपा को वोट देने का मतलब धोखेबाजों को संरक्षण देना है। रमन के पहले भाजपाइयों ने ही मोदी की गारंटी को कूड़ा दान में फेंक दिया है भाजपा के नेता खुद कह रहे हैं कि मोदी ने 15 लाख रु.दो करोड़ रोजगार, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा पूरा नहीं किया 12000 रु. की कोई गारंटी नहीं है।पूर्व रमन सरकार ने किसानों को धान की कीमत 2100 रु. प्रति क्विंटल 300 रु. बोनस बेरोजगारों को भत्ता, आदिवासियों को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा को पूरा किया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के रमन भाजपा शासन काल के दौरान एक लाख करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया। रमन सिंह के दमाद ने सरकारी डीके अस्पताल को गिरवी रखकर गड़बड़ियाँ की, रमन मेडिकल स्टोर के पता पर अभिषाक सिंह ने पनामा में खाता खुलवाया। रमन सिंह के परिजनों और भाजपा नेताओं के संरक्षण में चिटफंड कंपनियों ने गरीब जनता से 6000 करोड रु. लुटे, 20 लाख फर्जी राशनकार्ड बनाकर 36000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला हुआ। चावल में हेरा फेरी करके मैडम सीएम, सीएम सर ऐश्वर्या रेजिडेंसी तक पैसा पहुंचाया गया। स्काईवाक घोटाला, एक्सप्रेसवे घोटाला, आँखफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड हुआ।

शहरी-ग्रामीण दोनों वर्ग के मतदाता कांग्रेस के साथः शुक्ला

रायपुर। घोषणा पत्र के 21 वादों पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा था वह किया और जो किया उससे बढ़कर कांग्रेस आने वाले समय में जनता के लिये करने को प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में जनता को राहत देना और जनता का सर्वांगीण विकास है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य कांग्रेस की प्राथमिकता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शहरी और ग्रामीण दोनो का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ प्रदेश के लगभग 50 लाख परिवारों को मिलेगा। अभी तक गरीबी रेखा के नीचे के लोगो को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलता था तथा अन्य वर्ग के 50 हजार तक इलाज की सुविधा थी। कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीबी रेखा के नीचे वालों को 10 लाख तक तथा अन्य सभी वर्ग के लोगों को 5 लाख तक इलाज की मुफ्त सुविधा दी जायेगी। बड़ी बीमारियों में कांग्रेस की सरकार बनने पर 25 लाख तक ईलाज बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलेगा।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने कांग्रेस का लक्ष्य है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की शिक्षा नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी वर्ग के लिये निःशुल्क करने का वादा किया है।

भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है : उसेंडी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने विधानसभा चुनाव मंत भाजपा की शानदार जीत का दावा करते हुए कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश की मातृ-शक्ति सशक्तिकरण और मान-सम्मान के लिए महतारी वंदन योजना अमल में आएगी। सुश्री उसेंडी ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और प्रदेश में बनने जा रही भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ की मातृ-शक्ति को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को धरातल पर साकार करेगी।भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुश्री उसेंडी ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की महिलाओं से वादा किया है कि उसकी सरकार बनते ही महतारी वंदन योजना अमल में लाई जाएगी और इसके तहत प्रत्येक विवाहित महिला के बैंक खाते में 12 हजार रुपए सालाना जमा होंगे। यदि एक परिवार में दो विवाहित महिलाएँ हैं तो 24 हजार रु. सालाना, यदि तीन विवाहित महिलाएँ हैं तो 36 हजार रुपए सालाना मिलेंगे। इस प्रकार प्रति विवाहित महिला को पाँच सालों में 60 हजार रुपए मिलेंगे। इस मद के लिए भाजपा सरकार 42 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। इसका लाभ प्रदेश की सभी वर्ग की विवाहित महिलाओं को मिलेगा। सुश्री उसेंडी ने कहा कि इसी प्रकार बीपीएल परिवार के लिए रानी दुर्गावती योजना के तहत भाजपा की सरकार प्रत्येक जन्म लेने वाली बेटी के लिए 1.5 लाख रुपए का बॉण्ड जारी करेगी।

भाजपा के घमंड को चकनाचूर करने जनता तैयार है : वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यह मान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनावी मुकाबले में भूपेश पर भरोसे की सरकार के सामने बीजेपी के तमाम पैंतरे नाकाम रहे। भाजपा का पूरा चुनावी अभियान केवल झूठ और षड्यंत्र पर ही आधारित रहा। पूरे चुनावी अभियान के दौरान 15 साल के रमन सरकार की कोई उपलब्धि बता पाए और ना ही जिस मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं उस मोदी सरकार की साढ़े 9 साल की कोई उपलब्धि ही बता पाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर भाजपा नेताओं को भी स्पष्ट दिखाई दे रही है यही कारण है कि भाजपा के सांसद और तमाम नेता झूठी शिकायत और गलत बयानी करके संभावित हार के लिए अभी से बहाने तलाश रहे हैं। धनबल, बाहुबल और तमाम तरह के प्रलोभन से मतदाताओं को प्रभावित करने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है। आज भी पाली तानाखार के भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में साढ़े 11 लाख रुपए नगद बरामद हुए, कार्रवाई के दौरान भाजपा के प्रत्याशी उस गाड़ी में मौजूद थे। अपने ही कार्यकर्ताओं को बंधवा मजदूर समझने वाले भाजपाई छत्तीसगढ़ की जनता को भी प्रलोभन के झांसे में फासना चाहते है। पूरे प्रदेश में कई जगह बड़े पैमाने पर साड़ी, कपड़े, बिछिया, पायल, शराब, नगदी और कई तरह की सामग्री भाजपा नेताओं द्वारा बाटने के आरोप लगे हैं।

छत्तीसगढ़ की जनता जानती है किस पर भरोसा करना है: सीएम बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता का पिछले पांच बरसों में न केवल आत्मगौरव बढ़ा है बल्कि राजनीतिक चेतना भी बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि किस पर भरोसा करना है और कौन गारंटी के रूप में चुनावी जुमला फेंक रहा है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले पांच साल में जो काम किए हैं, यह चुनाव उसी पर जनमत संग्रह है और हमें विश्वास है कि इसमें हम खरे उतरेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी की मंशानुरुप कांग्रेस की सरकार ने वादा पूरा करने की शुरुआत शपथ ग्रहण के दो घंटे के भीतर ही कर दी थी और किसानों का कर्ज माफ़ किया था। इसके बाद 2500 रुपए में धान खरीदी से लेकर बेरोजगारी भत्ता देने तक बहुत से ऐसे काम किए जिनसे जनता को भरोसा हुआ कि कांग्रेस वादे से अधिक देती है। उन्होंने कहा है कि पिछले पांच वर्षों में किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की जनता की जेबों में पिछले पांच साल में पौने दो लाख करोड़ रुपए गए हैं।

और इसका असर यह हुआ है कि प्रदेश में न केवल संपन्नता बढ़ी और 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। बल्कि प्रदेश में कारोबार और उद्योग भी फले फूले हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दूसरी ओर भाजपा है जिसने प्रदेश की जनता के साथ धोखा ही किया। न किसानों को वादे के मुताबिक 2100 रुपए कीमत दी और न हर साल 300 रुपए का बोनस दिया। उन्होंने न हर आदिवासी परिवार को रोज़गार दिया और न उन्हें सुरक्षा दी। उन्होंने कहा है कि 15 साल के भाजपा शासनकाल में छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सल और गरीब प्रदेश के रूप में ही थी और कांग्रेस की सरकार ने सफलता पूर्वक इस पहचान को बदला है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पांच साल में ये फ़र्क पड़ा है कि अब छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या की भूमि, राम वन गमन पथ, आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को भाजपा के शासनकाल में भुला दिया गया था और अब हर छत्तीसगढ़वासी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व करता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भुरे ने की मतदान की अपील

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जिले के सभी मतदाताओं से विधानसभा निर्वाचन में अपना-अपना वोट अनिवार्यतः डालने की अपील की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों में वोट डाले जायेंगे।

डॉ. भुरे ने मतदान के लिए मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि मतदाता मतदान के लिए समय निकालकर अपने क्षेत्र के लिए निर्धारित मतदान केंद्रों में जरूर से मताधिकार का उपयोग करें। सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में प्रत्येक मतदाता का मत अमूल्य है तथा मतदान करना हर एक मतदाता का कर्तव्य है। डॉ. भुरे ने कहा कि जब मतदान के लिए जायें तो अपना मतदाता परिचय पत्र (एपिक कार्ड) एवं फोटो युक्त मतदाता पर्ची अवश्य लेकर जायें। मतदान केंद्र में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन के माध्यम से आप अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनने के लिए वोट कर सकते हैं। अपने जिला, राज्य एवं देश की खुशहाली के लिए एवं सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत मतदान का होना अपेक्षित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग सुनिश्चित करने की अपील सभी मतदाताओं से की है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मिडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.